

गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD, SURAT, LUCKNOW

वर्ष : 16
अंक : 192
दि. 10.11.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
AHMEDABAD EDITION

चीनी महिला से संबंधों के खुलासे के बाद एनवीडिया सीईओ विवादों में, हनीट्रैप के आरोपों की जांच शुरू

वॉशिंगटन। दुनिया की दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल एनवीडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेनसन हुआंग से जुड़ा एक विवाद अमेरिका में चर्चा का विषय बन गया है। एक चीनी महिला कारोबारी के साथ कथित संबंधों और पत्नी के प्रति बेवफाई स्वीकार करने के बाद हुआंग ने अपने परिवार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। इस पूरे घटनाक्रम ने उस समय और गंभीर रूप ले लिया, जब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि उनके करीब आई चीनी महिला कथित तौर पर बीजिंग के लिए गोपनीय सूचनाएं जुटाने के अभियान से जुड़ी हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एनवीडिया के निदेशक मंडल ने स्वतंत्र जांच शुरू कर दी है। वहीं, चीन ने अपने खिलाफ लगाए गए जासूसी साजिश के आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें देश की छवि खराब करने की कोशिश बताया है। इस प्रकरण में अब कंपनी के शीर्ष नेतृत्व, कारोबारी गोपनीयता और अंतरराष्ट्रीय खुफिया गतिविधियों से जुड़े कई सवाल उठ रहे हैं।

63 वर्षीय जेनसन हुआंग ने कंपनी के कर्मचारियों को भेजे ईमेल में अपने निजी जीवन से जुड़े घटनाक्रम पर गहरा अफसोस जताया। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की, जिससे उनके परिवार को दुख पहुंचा। हुआंग ने कहा कि अपने किए का कोई बहाना नहीं हो सकता और उन्हें इस बात का पछतावा है कि उनके फैसले से पत्नी और बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ी। उन्होंने परिवार से माफी मांगते हुए अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार किया। ईमेल में उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों, निदेशक मंडल और शेयरधारकों के प्रति अपनी जवाबदेही का भी उल्लेख किया। उन्होंने माना कि इस पूरे घटनाक्रम से उनके पेशेवर दायित्वों और लोगों के भरोसे पर सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही एनवीडिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए काम करने का आश्वासन दिया।

यह मामला उन मीडिया रिपोर्टों के बाद सुर्खियों में आया, जिनमें दावा किया गया था कि एक चीनी महिला कारोबारी ने जेनसन हुआंग के साथ नजदीकियां बढ़ाई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, महिला कथित तौर पर चीन की ओर से संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं जुटाने के प्रयास में शामिल हो सकती थी। इस महिला की पहचान हुआंग ले के रूप में बताई गई है। वह सिंगापुर



की डेटा सेंटर कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी रही है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उसका एनवीडिया सीईओ जेनसन हुआंग से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है। हालांकि, महिला की कथित भूमिका, उसके संपर्कों और किसी विदेशी खुफिया एजेंसी से संभावित संबंधों को लेकर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। इसलिए इस पूरे मामले को फिलहाल आरोपों और जांच के दायरे में ही देखा जा रहा है।

मामले में सबसे अहम पहलू यह है कि क्या एनवीडिया के संस्थापक और सीईओ को किसी विदेशी खुफिया अभियान के तहत निशाना बनाया गया था। यदि ऐसा हुआ है, तो इसका संबंध केवल उनके निजी जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कंपनी की कारोबारी सुरक्षा और संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता से जुड़े सवाल भी सामने आएंगे। एनवीडिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), चिप निर्माण और उन्नत कंप्यूटिंग तकनीक के क्षेत्र में दुनिया की प्रमुख कंपनियों में शामिल है। उसके उत्पादों और तकनीक की वैश्विक स्तर पर भारी मांग है। ऐसे में कंपनी के शीर्ष अधिकारी के संपर्कों और उनके माध्यम से संभावित रूप से संवेदनशील कारोबारी जानकारी तक पहुंच बनाने की किसी कोशिश को गंभीरता से लिया जा रहा है। इन्हीं परिस्थितियों के बीच एनवीडिया के निदेशक मंडल ने मामले की स्वतंत्र जांच कराने का फैसला किया है। जांच की निगरानी स्वतंत्र निदेशकों की एक समिति करेगी, ताकि पूरे प्रकरण की पड़ताल निष्पक्ष तरीके से हो सके। इसके लिए बाहरी कानूनी विशेषज्ञों की भी सहायता ली जाएगी। जांच में मीडिया रिपोर्टों में सामने आए आरोपों, संबंधित महिला की भूमिका और कंपनी के शीर्ष अधिकारी के साथ उसके संपर्कों से जुड़े पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या वास्तव में किसी विदेशी खुफिया अभियान के तहत हुआंग को निशाना बनाया गया था और क्या इस घटनाक्रम का कंपनी के कारोबारी हितों या गोपनीय सूचनाओं पर कोई असर पड़ा। जेनसन हुआंग ने निदेशक मंडल के इस फैसले का समर्थन किया है और जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा जताया है।

कंपनी के स्तर पर स्वतंत्र जांच शुरू होना इस बात का संकेत है कि एनवीडिया इस मामले को केवल अपने सीईओ के निजी जीवन से जुड़ा विवाद मानकर नहीं चल रही है। कंपनी के लिए यह पता लगाना भी जरूरी है कि कहीं किसी व्यक्ति ने निजी संबंधों का इस्तेमाल कर कारोबारी या तकनीकी जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिश तो नहीं की। हालांकि, अभी तक उपलब्ध जानकारी में किसी गोपनीय दस्तावेज के लीक होने या कंपनी के तकनीकी रहस्यों तक अनधिकृत पहुंच बनाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि जासूसी से जुड़े दावों में कितनी सच्चाई है और कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था पर इसका कोई वास्तविक प्रभाव पड़ा है या नहीं।

इस बीच चीन ने भी इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने सोमवार को एनवीडिया के सीईओ को निशाना बनाने के लिए जासूसी की साजिश रचे जाने के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने इन दावों को निराधार बताते हुए कहा कि यह चीन को बदनाम करने की कोशिश है। चीन की इस प्रतिक्रिया के बाद मामला अमेरिका और चीन के बीच पहले से जारी तकनीकी प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी चर्चा में आ गया है। दोनों देशों के बीच उन्नत चिप, एआई तकनीक और रणनीतिक तकनीकी संसाधनों को लेकर लंबे समय से प्रतिस्पर्धा बनी हुई है। ऐसे माहौल में किसी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनी के प्रमुख से जुड़े जासूसी के आरोपों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संवेदनशील माना जा रहा है।

फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के दो अलग-अलग पहलू सामने हैं। पहला, जेनसन हुआंग ने अपने निजी संबंधों और पत्नी के प्रति बेवफाई को स्वीकार करते हुए परिवार से माफी मांगी है। दूसरा, उनके करीब आई चीनी महिला को लेकर सामने आए कथित जासूसी संबंधी दावों की जांच की जा रही है। इन दोनों पहलुओं को आपस में जोड़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। एनवीडिया के निदेशक मंडल की स्वतंत्र जांच से ही यह साफ हो सकेगा कि क्या हुआंग किसी विदेशी खुफिया अभियान का निशाना बने थे या मामला मीडिया रिपोर्टों में लगाए गए आरोपों तक सीमित है। जांच के नतीजों पर कंपनी के कर्मचारियों, निवेशकों और वैश्विक तकनीकी उद्योग की नजर बनी रहेगी।

यूक्रेन का रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला, कई विस्फोटों के बाद लगी आग

मॉस्को। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में ऊर्जा ठिकाने लगातार निशाने पर बने हुए हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने रातभर किए गए ड्रोन हमले में रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। लेनिनग्राद क्षेत्र के किरिशी शहर में स्थित किनेफ रिफाइनरी परिसर में हमले के बाद कई बड़े विस्फोट हुए और आग लग गई। इस हमले से रूस के ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। दूसरी ओर, लेनिनग्राद क्षेत्र के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजदेंको ने दावा किया कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियों ने क्षेत्र में यूक्रेन के 81 ड्रोन मार गिराए हैं। हालांकि, रिफाइनरी को हुए वास्तविक नुकसान और उसके संचालन पर पड़े प्रभाव का पूरा आकलन सामने आना बाकी है।

हमले का निशाना किरिशी पेट्रोलियम ऑर्गेनिक सिंथेसिस संयंत्र था, जिसे किनेफ रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है। यह संयंत्र यूक्रेन से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमले के बाद रिफाइनरी परिसर में विस्फोटों और आग की खबरें सामने आईं। आग की गंभीरता का संकेत अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के फायर इंफॉर्मेशन फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एफआईआरएमएस) के उपग्रह आंकड़ों से भी मिला। इन आंकड़ों में रिफाइनरी क्षेत्र में आग और असामान्य गर्मी के कई केंद्र दर्ज किए गए। उपग्रह से मिले संकेतों ने



हमले के बाद परिसर में आग लगने की स्थिति की पुष्टि करने में मदद की, हालांकि उनसे अकेले नुकसान की कुल मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती।

किनेफ रिफाइनरी रूस के तेल प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती है। इसकी वार्षिक तेल शोधन क्षमता करीब दो करोड़ मीट्रिक टन बताई जाती है। रूस के कुल परिष्कृत तेल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी छह प्रतिशत से अधिक है। यहां कच्चे तेल को परिष्कृत कर विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा रूसी सेना के इस्तेमाल के लिए भी ईंधन का उत्पादन किया जाता है। ऐसे में इस संयंत्र पर हमला केवल एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर रूस की ऊर्जा आपूर्ति और सैन्य रसद व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यदि रिफाइनरी की प्रमुख इकाइयों को नुकसान पहुंचता है और उत्पादन प्रभावित होता है, तो पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है।

रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले पिछले कुछ समय से युद्ध की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। यूक्रेन की ओर से रूसी ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का उद्देश्य रूस की ईंधन उत्पादन क्षमता और युद्ध से जुड़ी आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित करना माना जाता है। किनेफ रिफाइनरी भी पहले यूक्रेनी ड्रोन हमलों का सामना कर चुकी है। इससे पहले पांच मई को हुए हमले में संयंत्र की चार में से तीन कच्चे तेल आसवन इकाइयों को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई थी। उस घटना के बाद रिफाइनरी में तेल शोधन का काम अस्थायी रूप से रोकना पड़ा था। इस बार हुए हमले ने संयंत्र की सुरक्षा और भविष्य में उसके संचालन को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं।

किनेफ रिफाइनरी पर अमेरिका सहित पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों का उद्देश्य उसकी आर्थिक और औद्योगिक क्षमता पर दबाव बनाना रहा है। इसके बावजूद रूस अपने तेल उत्पादन और प्रसंस्करण ढांचे को संचालित रखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में रिफाइनरियों पर बार-बार होने वाले ड्रोन हमले उसके ऊर्जा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त चुनौती बनते जा रहे हैं। तेल रिफाइनरी जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हमले से केवल उत्पादन ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि आग, विस्फोट और पर्यावरणीय नुकसान का खतरा भी पैदा होता है।

यह हमला ऐसे समय हुआ है, जब रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाने से रोकने के लिए युद्धविराम की संभावनाओं पर बातचीत की कोशिशें जारी रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने के लिए समझौता कराने की पहल की थी। इस प्रस्ताव का उद्देश्य तेल रिफाइनरियों, बिजली संयंत्रों और अन्य महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे पर हमलों को रोककर तनाव कम करना था। हालांकि, इस दिशा में स्थायी सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। 'द कीव इंडिपेंडेंट' की रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेन के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले अस्थायी रूप से रोकने के किसी समझौते पर कीव ने औपचारिक सहमति नहीं दी थी। इससे संकेत मिलता है कि ऊर्जा ठिकानों को लेकर युद्धविराम की कोशिशों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच मतभेद बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं।

48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर सरकारी कर्मचारी स्वतः निलंबित

नई दिल्ली। सरकारी सेवा में कार्यरत किसी कर्मचारी को गिरफ्तार किए जाने के बाद यदि वह लगातार 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे नियमानुसार स्वतः निलंबित माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानूनी प्रावधान को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति में कर्मचारी का निलंबन स्वतः प्रभावी हो जाता है। इसे डीम्ड सस्पेंशन कहा जाता है। अदालत ने यह टिप्पणी बिहार के समस्तीपुर स्थित सदर अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह से जुड़े जमानत मामले की सुनवाई के दौरान की।

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने विश्वजीत सिंह की जमानत बहाल कर दी। साथ ही पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जमानत मिलने के करीब एक वर्ष बाद उनकी जमानत निरस्त कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के तथ्यों और संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार करते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ ने अपने छह नवंबर के आदेश में कहा कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो सेवा नियमों के तहत उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। विश्वजीत सिंह पर आरोप था कि उन्होंने



सदर अस्पताल में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी का बकाया वेतन जारी करने के बदले चार हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी। संबंधित कर्मचारी का कुल बकाया वेतन 36,421 रुपये बताया गया था। इसी मामले में सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी कार्रवाई की गई थी और उन्हें हिरासत में लिया गया था। मामला आगे बढ़ने के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन लगभग एक साल बाद पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। इस आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर भी गौर किया कि विश्वजीत सिंह को पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन का आदेश वापस ले लिया गया। पीठ ने 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहने पर लागू होने वाले डीम्ड सस्पेंशन के प्रावधान का उल्लेख करते हुए मामले के इस पहलू को भी ध्यान में रखा।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों और गिरफ्तारी के बाद लागू होने वाले अनुशासनात्मक प्रावधानों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सेवा नियमों में 48 घंटे से अधिक हिरासत की स्थिति को विशेष महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गंभीर आपराधिक मामलों में हिरासत में रहने वाले कर्मचारियों की सेवा स्थिति नियमों के अनुरूप निर्धारित हो। डीम्ड सस्पेंशन का अर्थ है कि कर्मचारी को अलग से निलंबित करने का आदेश जारी होने की प्रतीक्षा किए बिना, निर्धारित परिस्थितियों में निलंबित माना जाता है। हालांकि, इस प्रावधान का संबंध कर्मचारी की सेवा स्थिति से है, इसे अपराध में दोष सिद्ध होने के समान नहीं माना जा सकता। गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत अपने आप में किसी व्यक्ति को दोषी साबित नहीं करती। मामले में आरोपों की कानूनी प्रक्रिया और सेवा संबंधी कार्रवाई अलग-अलग पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने विश्वजीत सिंह को जमानत बहाल करने के साथ ही 48 घंटे से अधिक हिरासत में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू डीम्ड सस्पेंशन के नियम को भी रेखांकित किया है।

हर तीसरा छात्र बुलिंग का शिकार, एआई से बढ़ रहा साइबर उत्पीड़न का खतरा

वाशिंगटन। दुनिया भर में स्कूल जाने वाले बच्चों के सामने डराने-धमकाने, अपमानित करने और मानसिक रूप से परेशान किए जाने की समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि दुनिया में हर तीन में से एक छात्र को हर महीने किसी न किसी रूप में बुलिंग यानी डराने-धमकाने या परेशान करने का सामना करना पड़ता है। वहीं, हर दस में से एक विद्यार्थी साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। चिंता की बात यह है कि डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल ने बच्चों को परेशान करने के नए रास्ते खोल दिए हैं। अब उत्पीड़न केवल स्कूल के कक्षों, खेल के मैदानों या रास्तों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। यूनेस्को ने चेतावनी दी है कि एआई आधारित तकनीकों के दुरुपयोग से बच्चों की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है।

यूनेस्को की नीति रिपोर्ट 'कनेक्टेड एंड सेफ' में बताया गया है कि डिजिटल दुनिया में बच्चों के खिलाफ उत्पीड़न के तरीके लगातार बदल रहे हैं। पहले जहां बुलिंग का स्वरूप मुख्य रूप से शारीरिक हिंसा, अपमानजनक



टिप्पणियों, धमकियों और सामाजिक बहिष्कार तक सीमित रहता था, वहीं अब तकनीक के जरिए इसे अधिक व्यापक और खतरनाक बनाया जा रहा है। एआई की मदद से किसी बच्चे की तस्वीरों को अश्लील या आपत्तिजनक रूप में तैयार किया जा सकता है। आवाज की नकल करने वाली तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की आवाज में झूठे संदेश या बातचीत तैयार की जा सकती है। इसके अलावा, कुछ एआई आधारित ऐप और डिजिटल टूल के माध्यम से परेशान करने वाले संदेश भेजने, फर्जी सामग्री तैयार करने और बच्चों को ऑनलाइन जाल में फंसाने जैसी गतिविधियों का खतरा भी बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के अनुसार, स्कूलों से जुड़े मामलों में अश्लील तस्वीरें बनाने वाले ऐप, आवाज की नकल करने वाली तकनीक और स्वचालित रूप से परेशान करने वाले संदेश भेजने वाले माध्यमों का दुरुपयोग चिंता का विषय बन रहा है। ऐसी तकनीक के जरिए किसी छात्र की छवि खराब करना, उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करना या उसकी निजी जिंदगी से जुड़ी झूठी सामग्री फैलाना आसान हो सकता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार कोई आपत्तिजनक तस्वीर, वीडियो या संदेश प्रसारित हो जाए तो उसे पूरी तरह हटाना भी मुश्किल हो जाता है। इससे पीड़ित बच्चे को बार-बार अपमान और मानसिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। कई बार ऑनलाइन उत्पीड़न स्कूल के समय के बाद भी जारी रहता है और बच्चे को घर पर भी मानसिक रूप से परेशान रखता है।

यूनेस्को की रिपोर्ट में यूरोप, मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका के 44 देशों में साइबर बुलिंग के बढ़ते मामलों का भी उल्लेख किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2022 के बीच इन देशों में साइबर बुलिंग का सामना करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 12 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि लड़कों और लड़कियों दोनों में दर्ज की गई। इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों का विस्तार बच्चों के लिए जहां शिक्षा और संवाद के नए अवसर लेकर आया है, वहीं इसके साथ ऑनलाइन उत्पीड़न का खतरा भी बढ़ा है। सोशल मीडिया पर किसी छात्र के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना, उसकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करना, फर्जी पहचान बनाकर संदेश भेजना या समूहों में उसका मजाक उड़ाना साइबर बुलिंग के सामान्य रूप बनते जा रहे हैं।

यूनेस्को के महानिदेशक खालिद अल-एनानी ने कहा कि इन आंकड़ों के पीछे लाखों बच्चों की जिंदगी जुड़ी हुई है। बुलिंग केवल बच्चों के बीच होने वाला सामान्य विवाद नहीं है, बल्कि यह उनकी पढ़ाई, स्वास्थ्य और खुशहाली को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डराने-धमकाने और अपमानित करने की घटनाओं का असर केवल स्कूल परिसर तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव बच्चों के आत्मविश्वास, सामाजिक व्यवहार और मानसिक स्थिति पर लंबे समय तक बना रह सकता है। लगातार प्रताड़ना झेलने वाले बच्चे पढ़ाई से दूरी बनाने लगते हैं, स्कूल जाने से डर सकते हैं और अपने दोस्तों तथा परिवार से भी बातचीत कम कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि बुलिंग का असर सभी बच्चों पर एक जैसा नहीं पड़ता। लड़कियां, दिव्यांग विद्यार्थी, अलग-अलग यौन रुझान और लैंगिक पहचान वाले बच्चे तथा सामाजिक रूप से हाशिये पर रहने वाले समूहों के विद्यार्थी इसकी चपेट में अधिक आते हैं। कई बार किसी बच्चे की शारीरिक बनावट, बोलने के तरीके, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पहचान को आधार बनाकर उसे निशाना बनाया जाता है। ऐसे बच्चों को एक साथ कई स्तरों पर भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ सकता है। इससे उनमें अकेलेपन, असुरक्षा और हीनभावना की स्थिति पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। यूनेस्को के अध्ययन के अनुसार, बुलिंग के स्वरूप में लड़के और लड़कियां अलग-अलग तरह से प्रभावित होते हैं। लड़कों को आमतौर पर शारीरिक हिंसा, धक्का-मुक्की और प्रत्यक्ष धमकियों का सामना अधिक करना पड़ता है। दूसरी ओर, लड़कियों को मानसिक उत्पीड़न, साइबर बुलिंग और उनके रूप-रंग को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों के जरिए निशाना बनाया जाता है। हालांकि, यौन प्रकृति की बुलिंग, जैसे अश्लील मजाक, आपत्तिजनक टिप्पणियां और अनुचित इशारे, लड़कों और लड़कियों दोनों को लगभग समान रूप से प्रभावित करते हैं। इस तरह का व्यवहार बच्चों के आत्मसम्मान और व्यक्तिगत सुरक्षा की भावना को चोट पहुंचा सकता है।

विशेषज्ञों के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है कि साइबर बुलिंग के कई मामले सामने ही नहीं आ पाते। बच्चे अक्सर डर, शर्मिंदगी या बदले की आशंका के कारण अपने माता-पिता और शिक्षकों को इसकी जानकारी नहीं देते। कई बार उन्हें लगता है कि शिकायत करने से स्थिति और बिगड़ सकती है या उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाएंगे। कुछ बच्चे ऑनलाइन मिलने वाली धमकियों और अपमानजनक संदेशों को सामान्य मानकर सहन करते रहते हैं। वहीं, माता-पिता को भी कई बार पता नहीं चल पाता कि उनका बच्चा डिजिटल माध्यमों पर किस तरह की परेशानी से गुजर रहा है। ऐसे में जरूरी है कि परिवार और स्कूल बच्चों के साथ भरोसे का संबंध बनाए रखें, ताकि वे बिना किसी डर के अपनी समस्या साझा कर सकें।

सूचना

हमारा कार्यालय नववर्षाभिनंदन, भाई दूज और तीज त्योहार के उपलक्ष्य में 10, 11 और 12 नवम्बर 26 को बंद रहेगा। इसलिए, समाचार पत्र 11, 12 और 13 नवम्बर को उपलब्ध नहीं होगा। अगला अंक 14 नवम्बर, 2026, शनिवार से यथावत प्रकाशित होगा।

- सम्पादक



संपादकीय

भाजपा और सपा के बीच बढ़ेगी सामाजिक समीकरणों की जंग

उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से हलचल तेज होने लगी है। सत्ता में वापसी के लिए भाजपा जहां अपने मजबूत संगठन, सरकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के सहारे चुनावी मैदान तैयार कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव सामाजिक गठबंधन को विस्तार देकर सत्ता में वापसी की संभावनाएं तलाश रहे हैं। प्रदेश की राजनीति में अब मुकाबला केवल भाजपा और सपा के बीच नहीं, बल्कि अलग-अलग जातीय और सामाजिक समूहों को अपने पाले में लाने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ का 80 प्रतिशत वाला राजनीतिक संदेश और अखिलेश यादव का 95 प्रतिशत आबादी को साथ लाने का प्रयास इसी बदलते राजनीतिक परिदृश्य के दो प्रमुख पहलू हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 80 बनाम 20 प्रतिशत का फॉर्मूला पेश किया था। उनके इस बयान को राजनीतिक विरोधियों ने धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़कर देखा, जबकि मुख्यमंत्री ने इसे विकास और सुशासन के समर्थकों तथा विरोधियों के बीच का अंतर बताया था। भाजपा ने इस नारे के जरिए अपने समर्थक वर्ग को एकजुट करने और व्यापक हिंदू मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश की। चुनाव में पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। अब 2027 के चुनाव से पहले भाजपा इसी रणनीति को नए सिरे से धार देने की तैयारी में है। हालांकि इस बार पार्टी के सामने चुनौती केवल अपने समर्थक आधार को एकजुट रखने की नहीं, बल्कि उन वर्गों की नाराजगी दूर करने की भी होगी, जो किसी कारणवश उससे दूरी बनाने की सोच रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी राजनीति का मुख्य आधार बनाया है। उनका 95 बनाम पांच प्रतिशत का संदेश समाज के उन बड़े वर्गों को एक मंच पर लाने की कोशिश है, जिन्हें वह राजनीतिक और सामाजिक रूप से पर्याप्त प्रतिनिधित्व से वंचित मानते हैं। समाजवादी पार्टी का मानना है कि यदि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और अन्य वंचित समूह एकजुट होते हैं तो भाजपा के मजबूत चुनावी आधार को चुनौती दी जा सकती है। हालांकि अखिलेश यादव अब केवल पीडीए के पारंपरिक दायरे तक सीमित नहीं रहना चाहते। उनकी नजर उन जातीय समूहों पर भी है, जिनका झुकाव लंबे समय से भाजपा की ओर रहा है। ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उनके प्रयास इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा माने जा रहे हैं। सामान्य वर्ग के मतदाताओं के बीच यूजीसी के दिशा-निर्देशों को लेकर उठी बहस ने भाजपा की चुनावी चिंता बढ़ाई है। इस मुद्दे पर समाज के एक हिस्से में असंतोष की चर्चा है। भाजपा के लिए यह स्थिति इसलिए संवेदनशील है क्योंकि सामान्य वर्ग के मतदाताओं का बड़ा हिस्सा लंबे समय से पार्टी के समर्थन में रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से जुड़े सीएसडीएस-लोकनीति के आंकड़ों में सामान्य वर्ग के करीब 77 प्रतिशत मतदाताओं का भाजपा के पक्ष में मतदान करने का अनुमान जताया गया था। ऐसे में यदि किसी नीति या निर्णय को लेकर इस वर्ग में नाराजगी बढ़ती है तो उसका असर कई विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। विपक्ष भी इसी संभावित असंतोष को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से यूजीसी के दिशा-निर्देशों के स्वरूप और उनके संतुलन को लेकर जताई गई चिंताओं की चर्चा ने इस विषय को और राजनीतिक बना दिया है। भाजपा और संघ के बीच बेहतर समन्वय को पार्टी की चुनावी सफलता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सीटें घटने के बाद संगठन और सरकार के बीच तालमेल को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई थीं। अब विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा किसी भी स्तर पर असंतोष को बढ़ने नहीं देना चाहती। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि संगठन, सरकार और सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल कायम रहे तथा सामाजिक समीकरणों को लेकर समय रहते रणनीति तैयार की जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की गोरखपुर में हुई कोर कमेटी की बैठक को भी आगामी चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी तथा संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसमें चुनावी तैयारियों, संगठन की मजबूती और विभिन्न सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भाजपा की रणनीति युवाओं को जोड़ने, प्रभावशाली सामाजिक नेताओं से संवाद बढ़ाने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता मजबूत करने की है।

रुपये में उतार-चढ़ाव के बीच RBI का बड़ा कदम, नई समिति का गठन

> आरबीआई ने वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच नई तकनीकी समिति बनाई है। जानिए रुपये, विदेशी मुद्रा भंडार और बॉन्ड बाजार पर इसका संभावित असर



भारतीय वित्तीय बाजारों में पिछले कुछ समय से जारी उतार-चढ़ाव और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों से पैदा हो रही चुनौतियों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। केंद्रीय बैंक ने वित्तीय बाजारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक तकनीकी परामर्श समिति का गठन किया है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, डेरिवेटिव बाजार और वित्तीय बाजारों के बुनियादी ढांचे से संबंधित नीतिगत एवं परिचालन संबंधी विषयों पर बाजार सहभागियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित तथा व्यवस्थित संवाद स्थापित करना है। इस पहल को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि समिति में अधिकांश सदस्य रिजर्व बैंक के बाहर से शामिल किए गए हैं। इससे केंद्रीय बैंक को बाजार की वास्तविक परिस्थितियों, कारोबारियों की समस्याओं और बदलती आर्थिक जरूरतों को समझने में मदद मिलेगी। साथ ही नीतिगत निर्णय लेने अथवा बाजार में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से पहले विभिन्न पक्षों से व्यापक जानकारी और व्यावहारिक सुझाव प्राप्त हो सकेंगे। दरअसल, पिछले कुछ महीनों में भारतीय वित्तीय बाजारों के सामने कई तरह की चुनौतियां एक साथ उभरकर आई हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव, पश्चिम एशिया में युद्ध की परिस्थितियां, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विदेशी निवेशकों की बदलती रणनीति और प्रमुख वैश्विक मुद्राओं की मजबूती ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दबाव बनाया है। इसका असर शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार में अलग-अलग रूपों में दिखाई दिया है। हालांकि शेयर और बॉन्ड बाजारों में भी अस्थिरता रही है, लेकिन रिजर्व बैंक का विशेष ध्यान रुपये की विनिमय दर और मुद्रा बाजार में स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित रहा है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में रुपये की स्थिति में कुछ सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से भारतीय मुद्रा पर लगातार दबाव बना हुआ है। डॉलर की मांग बढ़ने और विदेशी पूंजी के बाहर जाने से रुपये को संभालना केंद्रीय बैंक के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

भारत के सामने इस दौरान चालू खाते के घाटे में संभावित बढ़ोतरी के साथ-साथ पूंजी खाते से विदेशी धन की निकासी का दबाव भी रहा है। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है। इसी तरह विदेशी निवेशकों द्वारा भारतीय बाजारों से पूंजी निकालने पर डॉलर की मांग और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में घरेलू मुद्रा की कीमत पर दबाव पड़ना स्वाभाविक है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए यह चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे एक ओर आर्थिक विकास की गति बनाए रखनी है, वहीं दूसरी ओर रुपये की विनिमय दर में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को भी रोकना है। रिजर्व बैंक ने इस संतुलन को बनाए रखने के लिए समय-समय पर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। डॉलर की उपलब्धता बढ़ाने और रुपये में अचानक होने वाली गिरावट को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया है।

विदेशी निवेश को आकर्षित करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने स्वैप योजनाओं की भी घोषणा की। इन योजनाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवस्था में विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और रुपये की तरलता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि ऐसे उपाय तत्काल राहत देने में उपयोगी साबित हो सकते हैं, लेकिन इनके दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन करना भी जरूरी है। चार सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 785.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। इसके बाद इसमें करीब 66 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा भंडार में आई इस कमी को केवल एक कारण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसमें विनिमय दरों में बदलाव, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के मूल्यांकन और केंद्रीय बैंक के बाजार हस्तक्षेप जैसे कई कारकों की भूमिका होती है। फिर भी यह स्थिति बताती है कि वैश्विक परिस्थितियों के बीच रुपये को स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक को अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ा है। मुद्रा बाजार में अत्यधिक सट्टेबाजी को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक ने विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव बाजार में भी कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं। इनका उद्देश्य अनावश्यक सट्टा गतिविधियों को सीमित करना और बाजार में अस्थिरता को कम करना रहा है। हालांकि वित्तीय बाजारों में किसी भी तरह के प्रतिबंध का असर केवल सट्टेबाजों तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव उन कारोबारियों, निर्यातकों, आयातकों और कंपनियों पर भी पड़ सकता है, जो भविष्य में होने वाले मुद्रा विनिमय के जोखिम से बचने के लिए डेरिवेटिव साधनों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि बाजार में अनुशासन बनाए रखने और वास्तविक आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के बीच संतुलन कायम किया जाए। रिजर्व बैंक द्वारा गठित नई तकनीकी परामर्श समिति से इसी तरह के व्यावहारिक सुझाव मिलने की उम्मीद है। समिति का एक महत्वपूर्ण कार्य वित्तीय बाजारों को प्रभावित करने वाले उभरते नीतिगत और परिचालन संबंधी मुद्दों की पहचान करना होगा। इसमें रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपायों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने के साथ बाजार में पैदा होने वाली अनपेक्षित बाधाओं का पता लगाना भी शामिल है। अक्सर केंद्रीय बैंक किसी विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर कोई नीतिगत फैसला करता है, लेकिन उसके वास्तविक परिणाम बाजार के अलग-अलग हिस्सों में भिन्न हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी पर नियंत्रण लगाने के लिए किए गए किसी बदलाव से एक ओर जोखिम कम हो सकता है, तो दूसरी ओर निर्यातकों और आयातकों के लिए जोखिम प्रबंधन की लागत बढ़ सकती है। इसी प्रकार नकदी बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए उपायों का असर सरकारी बॉन्ड की कीमतों, ब्याज दरों और बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में किसी भी फैसले के व्यापक प्रभावों का समय रहते आकलन करना जरूरी है।

इस पूरे परिदृश्य में केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप की सीमा भी एक महत्वपूर्ण बहस का विषय रही है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान रिजर्व बैंक ने सरकारी बॉन्ड की बड़े पैमाने पर खरीद की। उपलब्ध आकलन के अनुसार, यह खरीद सकल घरेलू उत्पाद के करीब 2.5 प्रतिशत के बराबर थी और केंद्र सरकार के शुद्ध उधार का 80 प्रतिशत से भी अधिक बैठती थी। सरकारी बॉन्ड की खरीद से बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ती है और बॉन्ड की मांग बढ़ने के कारण उनकी कीमतों को समर्थन मिलता है। सामान्य तौर पर बॉन्ड की कीमतों और यील्ड के बीच विपरीत संबंध होता है। जब बॉन्ड की मांग बढ़ती है तो उनकी कीमतों में वृद्धि होती है और यील्ड में कमी आ सकती है। रिजर्व बैंक के इस हस्तक्षेप से सरकारी प्रतिभूतियों पर यील्ड को कुछ हद तक नीचे लाने में मदद मिली। इसके साथ ही अन्य बाजारों की तुलना में भारतीय बॉन्ड यील्ड का अंतर भी कम हुआ। हालांकि ब्याज दरों में इस तरह के बदलाव का विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी अध्ययन का विषय है। रिजर्व बैंक को सरकारी बॉन्ड खरीदने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप और पूंजी के देश से बाहर जाने के कारण बैंकिंग व्यवस्था में रुपये की नकदी की उपलब्धता प्रभावित हुई थी। विदेशी मुद्रा बाजार में जब केंद्रीय बैंक डॉलर बेचता है तो उसके बदले बाजार से रुपये की निकासी होती है। इससे बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध नकदी कम हो सकती है। दूसरी ओर, सरकारी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से केंद्रीय बैंक बाजार में रुपये की तरलता बढ़ाता है। इस प्रकार एक तरफ विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये को संभालने की कोशिश होती है, तो दूसरी तरफ घरेलू वित्तीय व्यवस्था में नकदी का संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। हालांकि हाल के दिनों में स्थिति में कुछ बदलाव देखने को मिला है। रिजर्व बैंक बाजार से अतिरिक्त नकदी को वापस लेने की दिशा में भी कदम उठाता रहा है। विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक यानी एफसीएनआर (बी) जमाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा आने से बैंकिंग प्रणाली में रुपये की तरलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक के सामने चुनौती केवल नकदी उपलब्ध कराने की नहीं, बल्कि जरूरत से अधिक नकदी को नियंत्रित करने की भी हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना पड़ रहा है। उसे रुपये की विनिमय दर, बैंकिंग प्रणाली की तरलता, सरकारी बॉन्ड की यील्ड और विदेशी निवेशकों के भरोसे के बीच संतुलन बनाए रखना है।

प्रेरणा

हाशिये के किरदारों की अनकही दुनिया को आवाज देतीं सशक्त कहानियां

साहित्य का वास्तविक उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं, बल्कि समाज के उन चेहरों और सच्चाइयों को सामने लाना भी है, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की चमक-दमक में अनदेखा कर दिया जाता है। लेखक सैली बलजीत का कहानी-संग्रह 'धूप में तलाश छांव की' इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। संग्रह में शामिल नौ लंबी कहानियां समाज के ऐसे लोगों की जिंदगी को केंद्र में रखती हैं, जो अभाव, भूख, शोषण और उपेक्षा के बीच अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन कहानियों के पात्र समाज के हाशिये पर खड़े वे लोग हैं, जिनकी पीड़ा आमतौर पर चर्चा का विषय नहीं बनती। संग्रह की कहानियां जीवन के उन कठोर अनुभवों से पाठक का सामना कराती हैं, जिनमें संवेदनाओं के साथ-साथ व्यवस्था की बेरुखी भी दिखाई देती है। लेखक ने अपने पात्रों को केवल दया का पात्र बनाकर प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उनके संघर्ष, विवशता, स्वाभिमान और जीवन के प्रति उनकी जिजीविषा को भी प्रभावशाली ढंग से उभारा है। यही वजह है कि इन कहानियों को पढ़ते हुए पाठक केवल घटनाओं से परिचित नहीं होता, बल्कि उनके पीछे छिपे सामाजिक यथार्थ पर भी विचार करने के लिए विवश होता है। संग्रह की एक कहानी में मौत के कुएं में करतब दिखाने वाले कलाकार की जिंदगी का मार्मिक चित्रण है। दर्शकों के मनोरंजन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाला यह कलाकार उस समय आग की लपटों में घिर जाता है, जब उसका खेल अचानक हादसे में बदल जाता है। जान बचाने के लिए उसकी चीख 'बिरजू, मुझे बचा लो!' केवल एक व्यक्ति की पुकार नहीं रह जाती, बल्कि उस असहाय इंसान की पीड़ा का प्रतीक बन जाती है, जिसकी जिंदगी दूसरों के मनोरंजन के लिए दांव पर लगी रहती है। तमाशा देखने वाली भीड़ और मौत से जूझते कलाकार के बीच का यह अंतर समाज की संवेदनहीनता को उजागर करता है।

एक अन्य कहानी बस विस्फोट की घटना के बाद पैदा होने वाली अमानवीय परिस्थितियों को सामने लाती है। हादसे में मारे गए यात्रियों के शवों और उनके सामान के बीच कुछ लोग ऐसी हरकतों में जुट जाते हैं, जो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। मृतकों के सामान को लूटने की प्रवृत्ति बताती है कि कुछ लोगों के लिए दूसरे की मौत भी स्वार्थ साधने का अवसर बन जाती है। लेखक इस प्रसंग के माध्यम से मानवीय मूल्यों के पतन और विपत्ति के समय सामने आने वाले समाज के विकृत चेहरे को रेखांकित करते हैं।

संग्रह में मुर्दाघर और पोस्टमार्टम से जुड़े कर्मचारी के जीवन को भी कथ्य बनाया गया है। सामान्य जीवन में जिन लोगों के काम को समाज बहुत कम समझता है, उनकी दिनचर्या, मानसिक स्थिति और पारिवारिक परिस्थितियों को लेखक ने संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। मृत्यु के बीच काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में भी सुख-दुख, रिश्ते, इच्छाएं और परेशानियां होती हैं। लेकिन समाज अक्सर उसके पेशे के आधार पर ही उसकी पहचान तय कर देता है। कहानी इस उपेक्षित वर्ग के मानवीय पक्ष को सामने लाती है। बहुरूपिया जैसे पारंपरिक लोक कलाकार का जीवन भी संग्रह की महत्वपूर्ण विषयवस्तु है। कभी लोगों के मनोरंजन और लोकसंस्कृति की पहचान रहे ऐसे कलाकार बदलते समय में अपनी जगह खोते जा रहे हैं। उनके सामने रोजी-रोटी का संकट है और कला के प्रति समाज की रुचि भी पहले जैसी नहीं रही। लेखक ने इस पात्र के माध्यम से उन परंपरागत कलाकारों की दुर्दशा को रेखांकित किया है, जिनकी कला कभी सामाजिक जीवन का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन आज वे उपेक्षा और आर्थिक तंगी के बीच जीने को मजबूर हैं। कहानियों में किन्नर समुदाय, छोटे-मोटे अपराधों में उलझे लोगों और भूख से जूझते गरीबों की जिंदगी भी स्थान पाती है। लेखक इन पात्रों को किसी एक सामाजिक पहचान में सीमित नहीं करते, बल्कि उनकी परिस्थितियों और संघर्षों को समझने की कोशिश करते हैं। समाज जिन लोगों को आसानी से अपराधी, उपेक्षित या असामान्य मानकर किनारे कर देता है, उनकी जिंदगी के पीछे मौजूद मजबूरियों को कहानियां उजागर करती हैं। इससे पाठक को यह सोचने का अवसर मिलता है कि किसी व्यक्ति की परिस्थितियों को समझे बिना उसके बारे में फैसला करना कितना उचित है। रेलवे प्लेटफार्मों पर रहने वाले बेघर लोगों की जिंदगी और उनसे की जाने वाली वसूली का प्रसंग भी व्यवस्था की संवेदनहीनता को सामने लाता है। जिन लोगों के पास सिर छिपाने के लिए अपना घर तक नहीं है, उन्हें सुरक्षित रहने के लिए भी तरह-तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है। गरीबी और बेबसी उनके जीवन को इस कदर घेर लेती है कि बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी संघर्ष बन जाता है। लेखक इस स्थिति को केवल आर्थिक समस्या के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे सामाजिक असमानता और मानवीय अधिकारों से जुड़ा प्रश्न बनाते हैं।

सैली बलजीत की विशेषता यह है कि वे अपने पात्रों की पीड़ा को भावुकता के सहारे नहीं, बल्कि जीवन के वास्तविक प्रसंगों के माध्यम से पाठक तक पहुंचाते हैं। कहानियों में घटनाओं का विस्तार, पात्रों की मनोदशा और परिवेश का चित्रण कथ्य को प्रभावशाली बनाता है। कई प्रसंग पाठक को भीतर तक झकझोरते हैं, क्योंकि वे किसी कल्पित दुनिया के बजाय हमारे आसपास मौजूद कठोर सच्चाइयों की याद दिलाते हैं।

'धूप में तलाश छांव की' शीर्षक भी संग्रह की मूल संवेदना को व्यक्त करता है। धूप यहां संघर्ष, अभाव और जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, जबकि छांव उस राहत, सम्मान और अपनत्व की तलाश है, जिसकी जरूरत हर इंसान को होती है। संग्रह की नौ कहानियां अलग-अलग पात्रों और परिस्थितियों के माध्यम से इसी तलाश को सामने रखती हैं। ये कहानियां बताती हैं कि समाज की असली तस्वीर केवल संपन्न और सुविधाभोगी वर्ग के जीवन से नहीं बनती, बल्कि उन लोगों के संघर्षों से भी बनती है, जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है।

ज़हरीली हवा का तांडव: भारत में श्वास और श्मशान के बीच का घटता फासला

भारत में सांस लेना अब महज जिंदा रहने का जरिया नहीं रह गया है, बल्कि यह धीरे-धीरे मौत का सबसे बड़ा और खामोश कारण बनता जा रहा है।सुबह की जो ताज़ी हवा किसी भी इंसान के भीतर नए जीवन और ऊर्जा का संचार करने के लिए होनी चाहिए, वह आज हमारे फेफड़ों में ज़हर घोल रही है। भारत के महानगरों से लेकर छोटे कस्बों तक, आसमान में छाई धुंध और हवा में तैरते बारीक कण (पीएम 2.5 और पीएम 10) इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम एक सामूहिक स्वास्थ्य आपातकाल के मुहाने पर खड़े हैं। यह संकट किसी एक मौसम या त्योहार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी आधुनिक जीवनशैली, लापरवाह नीतियों और सामूहिक असंवेदनशीलता का एक ऐसा चक्रव्यूह बन चुका है, जिसने हर नागरिक को असमय मौत के साए में जीने के लिए मजबूर कर दिया है। जब हम विकास की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी धमक का जश्न मनाते हैं, तब हमारी पीठ पीछे एक पूरी पीढ़ी फेफड़ों की गंभीर बीमारियों, दिल के दौरों और मानसिक अवसान की तरफ धकेली जा रही है। यह महज पर्यावरण का क्षरण नहीं है, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी है जिसे हम रोज़ थोड़ा-थोड़ा करके खुद ही लिख रहे हैं।

इस जानलेवा माहौल को बनाने में हमारे त्योहारों और उत्सवों के नाम पर होने वाली अति का एक बहुत बड़ा हाथ है। हर साल दिवाली, शादियों और अन्य सामाजिक समारोहों के दौरान देश भर में भारी मात्रा में जलने वाले पटाखे इस संकट को चरम पर पहुंचा देते हैं। पटाखों से निकलने वाला धुआं साधारण धुआं नहीं होता; इसमें तांबा, कैडमियम, सल्फर, एल्युमिनियम और बेरियम जैसे बेहद खतरनाक भारी तत्व होते हैं, जो हवा में हफ्तों तक तैरते रहते हैं। एक रात की आतिशबाजी और कुछ घंटों का दिखावटी मनोरंजन आने वाले कई महीनों के लिए हवा को सांस लेने के अयोग्य बना देता है। विडंबना यह है कि इसे हम अपनी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा मानकर सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जबकि कोई भी धर्म या परंपरा किसी मासूम के फेफड़ों को छलनी करने या नवजात शिशुओं को जन्म से ही अस्थमा का रोगी बनाने की इजाजत नहीं देता। पटाखों के इस बारूद ने हमारी चेतना को इस कदर सुन्न कर दिया है कि हम अगली सुबह सड़कों पर बिछी राख और सांस लेने में होने वाली तकलीफ को नियति मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यह एक ऐसा आत्मघाती व्यवहार है, जिसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां चुका रही हैं।उत्सवों के इस मौसमी प्रदूषण से इतर जो प्रदूषण हमारी रगों में हर सेकंड ज़हर भर रहा है, वह है हमारे शहरों की सड़कों पर अंधाधुंध दौड़ने वाले और धुआं उगलने वाले वाहन। सार्वजनिक परिवहन की लचर व्यवस्था और निजी वाहनों को प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने की सामाजिक होड़ ने भारतीय सड़कों को चलते-फिरते प्रदूषण के कारखानों में तब्दील कर दिया है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां, विशेषकर पुरानी कमर्शियल गाड़ियां और भारी ट्रक, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों का सबसे बड़ा स्रोत हैं। ट्रैफिक जाम में फंसी गाड़ियों का साइलेंसर जब लगातार धुआं फेंकता है, तो सड़कों के आसपास रहने वाले, पैदल चलने वाले और सबसे ज्यादा सुरक्षात्मक घेरे से बाहर रहने वाले गरीब तबके के लोग सीधे तौर पर मौत के इस धुएं को अपने भीतर खींचते हैं। वाहनों का यह धुआं हमारे शहरों की आबोहवा को इस कदर घोंट रहा है कि सर्दियों के दिनों में प्रदूषण का स्तर सुरक्षित मानकों से बीस से तीस गुना तक ऊपर चला जाता है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर चमचमाती सड़कें और फ्लाईओवर्स तो बना रहे हैं, लेकिन उन पर रेंगने वाली गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का कोई पुख्ता और टिकाऊ समाधान ढूंढने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं।

इस भयावह जमीनी हकीकत को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय ने भी बेहद गंभीरता से रेखांकित किया है। स्वीडन के विश्व प्रसिद्ध कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट की एक हालिया और बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च ने इस दिशा में ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं जो हमारी रूह को कंपा देने के लिए काफी हैं। इस स्वीडिश रिसर्च के अनुसार, केवल साल 2009 से 2019 के बीच के एक दशक में ही वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 38 लाख लोगों की असामयिक मौत हो गई। 38 लाख का यह आंकड़ा कोई साधारण संख्या नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी हवा एक मूक कातिल बन चुकी है जो युद्ध या महामारियों से भी ज़्यादा तेज़ी से इंसानी जिंदगियों को लील रही है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि भारत के प्रदूषित क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने वाले लोगों की औसतन जीवन प्रत्याशा में पांच से सात साल तक की भारी कमी आ रही है। इस शोध में यह भी खुलासा किया गया है कि हवा में मौजूद पीएम 2.5 के अति सूक्ष्म कण सीधे हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं और मस्तिष्क तथा हृदय तक पहुंचकर कम उम्र के लोगों में स्ट्रोक, कार्डियक अरेस्ट और अल्जाइमर जैसी घातक न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का कारण बन रहे हैं। स्वीडन के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भारत ने तुरंत अपने वायु गुणवत्ता मानकों में क्रांतिकारी सुधार नहीं किए, तो स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ देश की जीडीपी को खोखला कर देगा। यह रिसर्च हमें यह समझने के लिए मजबूर करती है कि प्रदूषण अब सिर्फ एक दृश्य संकट नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य हत्यारा है जो हमारे घरों की चारदीवारी के भीतर भी सुरक्षित नहीं रहने दे रहा है।

अभियान

श्रीकृष्ण की भक्ति से जीवन में आती है सुख, शांति और समृद्धि की मधुर अनुभूति

सनातन धर्म में भगवान श्रीकृष्ण को प्रेम, करुणा, ज्ञान, धर्म और लोककल्याण का प्रतीक माना गया है। उनका संपूर्ण जीवन मानवता को जीवन जीने की कला सिखाता है। बचपन की मनमोहक लीलाओं से लेकर महाभारत के युद्धक्षेत्र में दिए गए श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेशों तक, भगवान कृष्ण का प्रत्येक स्वरूप भक्तों को कोई न कोई संदेश देता है। वे कहीं नटखट बाल गोपाल के रूप में भक्तों के मन को आनंदित करते हैं, तो कहीं मुरलीधर बनकर प्रेम और माधुर्य का संदेश देते हैं। वहीं कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कर्म, धर्म और कर्तव्य का ज्ञान देकर जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्रीकृष्ण की इसी दिव्य महिमा और कृपा का गुणगान करने वाला एक लोकप्रिय भक्तिपाठ श्रीकृष्ण चालीसा है। मान्यता है कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका नियमित पाठ करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, धैर्य तथा आत्मविश्वास का संचार होता है।

श्रीकृष्ण चालीसा में भगवान के स्वरूप, उनकी बाल लीलाओं, दिव्य गुणों, भक्तों के प्रति प्रेम और धर्म की स्थापना के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन मिलता है। चालीसा का अर्थ सामान्य रूप से चालीस चौपाइयों या छंदों वाले भक्तिपाठ से जुड़ा है। इसमें भगवान के विभिन्न रूपों और उनके गुणों का स्मरण किया जाता है। भक्त जब इसका पाठ करते हैं तो उनका मन सांसारिक चिंताओं से हटकर प्रभु के चरणों में एकाग्र होने लगता है। यही एकाग्रता धीरे-धीरे मन में शांति और भक्ति का भाव विकसित करती है। कृष्ण भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें प्रेम, समर्पण और सहजता को विशेष महत्व दिया गया है। भगवान श्रीकृष्ण के लिए भक्त की भावना और उसका निष्कपट प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण माना गया है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रीकृष्ण चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना शुभ माना जाता है। विशेष रूप से सुबह स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान कृष्ण के सामने दीपक जलाकर इसका पाठ करना भक्तों के लिए पुण्यकारी माना जाता है। पूजा के समय भगवान के बाल स्वरूप, लड्डू गोपाल, राधा-कृष्ण या मुरलीधर स्वरूप का ध्यान किया जा सकता है। पूजा स्थल पर स्वच्छता बनाए रखना और मन को शांत रखना भी महत्वपूर्ण है। पाठ करते समय जल्दबाजी करने के बजाय प्रत्येक चौपाई के भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे भक्त का ध्यान भगवान के गुणों और उनकी लीलाओं पर केंद्रित होता है। यदि किसी दिन पूरा पाठ करना संभव न हो तो अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार भगवान का नाम स्मरण भी किया जा सकता है। भक्ति में दिखावे से अधिक भावना और समर्पण का महत्व माना गया है।

भगवान श्रीकृष्ण के जीवन की बाल लीलाएं भक्तों के हृदय में विशेष स्थान रखती हैं। गोकुल और वृं

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में सूरत में दीपावली एवं नूतन वर्ष स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने विक्रम संवत 2083 के नववर्ष के अवसर पर सभी नागरिकों तथा दिन-रात कर्तव्य निभाने वाले कर्मयोगियों को शुभकामनाएँ दीं

गांधीनगर : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की प्रेरक उपस्थिति में सूरत शहर के महाराजा अग्रसेन भवन में सोमवार को दीपावली एवं विक्रम संवत 2083 के नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने पूरे गुजरात के नागरिकों के साथ-साथ त्योहारों के दिनों में भी अपने परिवार से दूर रहकर निष्ठापूर्वक कर्तव्य निभाने वाले कर्मयोगियों को दीपावली और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।



उप मुख्यमंत्री ने सभी से अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा के संवर्धन के लिए सभी व्यवहारों और लेखन में 'विक्रम संवत' कैलेंडर का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी कैलेंडर पद्धति की तुलना में हमारी पंचांग-कैलेंडर पद्धति खगोलीय गणनाओं, ऋतुओं और तिथियों से जुड़ी अत्यंत वैज्ञानिक एवं समृद्ध विरासत है। वर्षों पुरानी इस गौरवपूर्ण वैज्ञानिक विरासत को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

दीपावली पर्व के दौरान आम नागरिक अपने परिवार के साथ निर्भयता और आनंदपूर्वक त्योहार मना सकें, इसके लिए लगातार कार्यरत पुलिस विभाग, महानगर पालिका के स्वच्छतादूतों, जीएसआरटीसी के ड्राइवर-कंडक्टर और फायर ब्रिगेड के जवानों की समर्पित सेवाओं की विशेष रूप से सराहना की। दिन-रात एक करके नागरिकों की सुरक्षा और सुविधाएँ बनाए रखने वाले इन कर्मयोगियों की निष्ठा ही राज्य के विकास की वास्तविक शक्ति है। ऐसा बताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में एसटी के राजस्व में लगातार हो रही वृद्धि के साथ गुजरात तेजी से विकास की नई ऊँचाइयाँ प्राप्त कर रहा है।

उन्होंने नववर्ष के प्रारंभ में अतीत के सभी मतभेदों को भुलाकर, नए बही-खाते की तरह नए संबंधों की शुरुआत करते हुए राज्य के जनकल्याण के लिए एक टीम के रूप में कार्यरत रहने का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से पुलिस थानों और पुलिस आवासों के परिसरों को राज्य में सबसे स्वच्छ, सुव्यवस्थित और आदर्श बनाने पर जोर दिया। इस स्नेह मिलन समारोह में जिला कलेक्टर श्री तेजस परमार, महानगर पालिका आयुक्त श्री राजकुमार बेनीवाल तथा पुलिस आयुक्त श्री वाबांग झमीर उपस्थित रहे। उन्होंने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएँ दीं तथा शहर और जिले को प्रगति की नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए टीमवर्क के साथ कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम के बाद उप मुख्यमंत्री ने मीडिया कर्मियों तथा संगठन के कार्यकर्ताओं से सद्भावना भेंट की और नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया।

इस अवसर पर सूडा के सीईओ श्री राज सुथार, अपर पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) श्री सज्जनसिंह परमार, सूरत रेंज आईजी श्री प्रेमवीरसिंह, अपर पुलिस आयुक्त श्री करणराज वाघेला, श्री बलराम मीणा, जिला प्रशासन, सूरत महानगर पालिका, पुलिस विभाग, जीएसआरटीसी और आरटीओ विभाग के उच्च अधिकारी-कर्मचारी तथा सामाजिक-राजनीतिक अग्रणी उपस्थित रहे।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में इस्कॉन-साणंद एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण किया

गांधीनगर : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सोमवार को अहमदाबाद में इस्कॉन जंक्शन से साणंद फ्लाईओवर तक नवनिर्मित इस्कॉन-साणंद एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, अहमदाबाद के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, विधायक श्री अमितभाई ठाकर और श्री बाबुभाई पटेल सहित महानुभाव उपस्थित रहे।



नूतन वर्ष के प्रारंभ से पूर्व यातायात के लिए खोला गया यह 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर अहमदाबाद के नागरिकों और वाहन चालकों के लिए एक बेहतरीन भेंट साबित होगी। सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर लगातार बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से तैयार किए गए इस कॉरिडोर से नागरिकों को ट्रैफिक जाम की समस्या से स्थायी मुक्ति मिलेगी तथा समय और ईंधन की भी बड़ी बचत होगी। सरखेज से गांधीनगर के बीच का संपर्क अब पूरी तरह बाधारहित और सुरक्षित बनेगा। उल्लेखनीय है कि सरखेज-गांधीनगर हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 147) पर कर्णावती क्लब, प्रह्लादनगर और वायएमसीए जैसे अत्यंत व्यस्त जंक्शनों से होकर गुजरने वाला यह कॉरिडोर यातायात के प्रवाह को सुगम बनाएगा। यात्रा का समय कम होने के साथ ही वाहन संचालन लागत (वीओसी) में कमी आएगी; जिससे आर्थिक लाभ होगा। इसके अलावा, सड़क सुरक्षा के आधुनिक प्रावधानों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आएगी और हाईवे पर यात्रा अधिक सुरक्षित बनेगी।

भारत सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमानित 464 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया 4.03 किलोमीटर लंबा और 26.8 मीटर चौड़ा यह 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें वायाडक्ट की लंबाई 2,940 मीटर और एप्रोच की लंबाई 1,090 मीटर है। फ्लाईओवर से गुजरने वाले वाहनों के शोर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 5,880 मीटर लंबाई में विशेष नॉइज बैरियर लगाए गए हैं। सुरक्षा और सुविधा के लिए 297 स्ट्रीट लाइटें, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ओवरहेड और कैंटिलीवर गैन्ट्री, रोड सेफ्टी बोर्ड, कैट आई, एंटी-ग्लेयर तथा 7 से 14 मीटर चौड़ाई वाले व्हाइटटॉपिंग सर्विस रोड बनाए गए हैं।

इस्कॉन-साणंद एलिवेटेड कॉरिडोर के लोकार्पण समारोह में अहमदाबाद नगर निगम आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, अहमदाबाद नगर निगम के पदाधिकारी, स्थानीय पार्षद, सामाजिक एवं राजनीतिक अग्रणी उपस्थित रहे।

कैंसर की 1,364 दवाओं के दाम घटे, मरीजों को सालाना 3,540 करोड़ की बचत का अनुमान

नई दिल्ली। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च कम करने की दिशा में केंद्र सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। देशभर में कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली 1,364 दवाओं के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) सोमवार, 9 नवंबर से प्रभावी हो गए हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की ओर से किए गए इस मूल्य संशोधन के बाद मरीजों और उनके परिवारों को सालाना करीब 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। दवाओं की कीमतों में इस कटौती से कैंसर के इलाज पर होने वाला आर्थिक बोझ कम हो सकता है। खासतौर पर उन मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें लंबे समय तक दवाओं का सेवन करना पड़ता है और जिनके उपचार में लगातार बड़ी रकम खर्च होती है।



रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अनुसार, एनपीपीए ने कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली 137 दवाओं के व्यापार मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया था। इस व्यवस्था के बाद दवा कंपनियों को संबंधित दवाओं की कीमतों में संशोधन करना पड़ा। मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक, 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं के कुल 1,364 फॉर्मूलेशन के संशोधित मूल्य घोषित कर दिए थे। इन्हीं संशोधित कीमतों को 9 नवंबर से लागू किया गया है। इसका मतलब है कि अब संबंधित दवाएं बाजार में नई निर्धारित एमआरपी के अनुसार ही बेची जानी हैं।

इस मूल्य नियंत्रण व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दवाओं की बिक्री में शामिल व्यापारिक मार्जिन को एक निर्धारित सीमा के भीतर रखा गया है। दवाओं के निर्माण से लेकर मरीज तक पहुंचने की प्रक्रिया में कंपनियों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं की अलग-अलग भूमिका होती है। इस पूरी व्यवस्था में व्यापारिक मार्जिन का असर अंतिम कीमत पर पड़ता है। एनपीपीए ने 137 कैंसर रोधी दवाओं के मामले में इस मार्जिन को अधिकतम खुदरा मूल्य के 30 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी को रोकना और मरीजों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपचार संबंधी दवाएं उपलब्ध कराना है।

मंत्रालय के अनुसार, कीमतों में कटौती का असर बड़ी संख्या में दवा ब्रांडों पर पड़ा है। कुल 679 ब्रांड की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत से अधिक घटाए गए हैं। कुछ दवाओं की कीमतों में अधिकतम 96.45 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है। यह कटौती कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न फॉर्मूलेशन पर लागू हुई है। इससे मरीजों को पहले की तुलना में काफी कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। हालांकि, अलग-अलग ब्रांड और फॉर्मूलेशन के अनुसार कीमतों में कमी का स्तर अलग-अलग है। इसलिए मरीजों को दवा खरीदते समय उसके पैकेट पर दर्ज संशोधित एमआरपी की जांच करना जरूरी होगा।

कैंसर का उपचार अक्सर लंबी अवधि तक चलता है। बीमारी की स्थिति, उपचार की पद्धति और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार मरीजों को अलग-अलग दवाओं की जरूरत पड़ती है। कई मामलों में दवाओं का नियमित सेवन और बार-बार उपचार कराना पड़ता है, जिससे परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में कमी केवल एक बार की खरीद तक सीमित राहत नहीं देती, बल्कि लंबे उपचार के दौरान होने वाले खर्च को भी प्रभावित कर सकती है। सरकार की ओर से सालाना 3,540.38 करोड़ रुपये की संभावित बचत का अनुमान इसी व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

नई कीमतें लागू होने के बाद दवा विक्रेताओं, अस्पतालों से जुड़ी फार्मेसियों और अन्य खुदरा बिक्री केंद्रों के लिए संशोधित एमआरपी का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी दवा विक्रेता या अस्पताल की फार्मेसी संबंधित दवा के लिए निर्धारित नई अधिकतम खुदरा कीमत से अधिक रकम नहीं वसूल सकेगी। यदि किसी मरीज से संशोधित एमआरपी से अधिक कीमत ली जाती है, तो वह इसकी शिकायत संबंधित प्राधिकरण के समक्ष कर सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मूल्य नियंत्रण से मिलने वाला लाभ वास्तविक रूप से मरीजों तक पहुंचे और बीच की वितरण व्यवस्था में उसका लाभ समाप्त न हो।

दवाओं की नई कीमतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। मरीज दवा के पैकेट पर छपी संशोधित एमआरपी देख सकते हैं। इसके अलावा एनपीपीए के 'फार्मा सही दाम' मोबाइल ऐप और प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी दवाओं की निर्धारित कीमतों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दवा खरीदते समय मरीज या उनके परिजन संबंधित ब्रांड और फॉर्मूलेशन का मूल्य जांच सकते हैं। इससे बाजार में उपलब्ध दवाओं की वास्तविक कीमत और निर्धारित एमआरपी के बीच अंतर का पता लगाना आसान होगा।

यदि किसी दवा विक्रेता या अस्पताल की फार्मेसी की ओर से नई निर्धारित कीमत से अधिक रकम वसूली जाती है, तो उपभोक्ता 'फार्मा जन समाधान' पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एनपीपीए ने 1800-111-255 हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई है। इस माध्यम से मरीज और उनके परिजन दवाओं की अधिक कीमत वसूले जाने से जुड़ी शिकायत प्राधिकरण तक पहुंचा सकते हैं। मूल्य नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए शिकायत व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एनपीपीए की ओर से उठाया गया यह कदम कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को अधिक किफायती बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण के साथ यह भी जरूरी है कि मरीजों को निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध हों। नई दरें लागू होने के बाद अब निगरानी और शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। यदि संशोधित एमआरपी का प्रभावी ढंग से पालन होता है, तो दवाओं की कीमतों में हुई कटौती का लाभ बड़ी संख्या में कैंसर मरीजों और उनके परिवारों तक पहुंच सकेगा।

प्रदूषण से बेजान हुई त्वचा में फिर लौटाएं प्राकृतिक निखार

देश के अधिकांश शहरों में वायु प्रदूषण लगातार गंभीर समस्या बनता जा रहा है। आसमान में धूल, धुएं और हानिकारक गैसों से बनी धुंध की परत कई बार इतनी घनी हो जाती है कि लोगों को सांस लेने के साथ-साथ सामान्य रूप से देखने में भी परेशानी होने लगती है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि त्वचा और बालों की सुंदरता के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। आमतौर पर लोग प्रदूषण से होने वाले फेफड़ों और सांस संबंधी नुकसान के प्रति जागरूक रहते हैं, लेकिन इसका चेहरे की रंगत, त्वचा की नमी, बालों की चमक और संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लगातार प्रदूषित वातावरण में रहने से चेहरा मुरझाया हुआ, बेजान और थका-थका दिखाई देने लगता है। त्वचा का प्राकृतिक आकर्षण कम होने के साथ ही समय से पहले उम्र बढ़ने के लक्षण भी उभर सकते हैं।

शहरों में वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, कचरा जलाने से निकलने वाला धुआं और अन्य प्रदूषक वातावरण में मौजूद रहते हैं। इनके सूक्ष्म कण त्वचा की बाहरी सतह पर जम जाते हैं। पसीने और त्वचा के प्राकृतिक तेल के साथ मिलकर ये कण रोमछिद्रों को बंद कर सकते हैं। इससे त्वचा पर अतिरिक्त गंदगी जमा होने, मुंहासे निकलने और जलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। कुछ प्रदूषक त्वचा में ऑक्सीडेटिव तनाव पैदा करते हैं, जिससे त्वचा के प्राकृतिक कोलेजन और इलास्टिन को नुकसान पहुंच सकता है। यही कारण है कि लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से त्वचा की कसावट कम होने, महीन रेखाएं उभरने और झुर्रियां जल्दी दिखाई देने की आशंका बढ़ जाती है।

प्रदूषण के कारण त्वचा का प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। जिन लोगों की त्वचा पहले से संवेदनशील है, उन्हें खुजली, लालिमा, सूखापन और छोटे-छोटे दाने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तैलीय त्वचा वाले लोगों में रोमछिद्र बंद होने और मुंहासे बढ़ने की समस्या देखी जा सकती है, जबकि शुष्क त्वचा वालों को खिंचाव, रूखापन और पपड़ी जमने की शिकायत हो सकती है। प्रदूषण के साथ सूर्य की पराबैंगनी किरणों का संपर्क भी त्वचा को अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इससे चेहरे पर असमान रंगत, काले धब्बे और पिगमेंटेशन की समस्या बढ़ सकती है। इसलिए प्रदूषण के मौसम में त्वचा की देखभाल को सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गंभीरता से लेना चाहिए।

सबसे पहले त्वचा की नियमित और सही तरीके से सफाई करना जरूरी है। दिनभर बाहर रहने के बाद चेहरे पर धूल, धुआं, पसीना और अन्य प्रदूषक जमा हो जाते हैं। इन्हें हटाने के लिए रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। यदि आपकी त्वचा शुष्क है तो हल्के और सौम्य क्लींजिंग मिल्क या क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तैलीय त्वचा के लिए माइल्ड फेसवॉश बेहतर विकल्प हो सकता है। सामान्य और मिश्रित त्वचा वाले लोग अपनी त्वचा के अनुकूल क्लींजर चुनें। चेहरे को बार-बार तेज साबुन से धोने या जोर-जोर से रगड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत प्रभावित हो सकती है। सफाई के बाद त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर लगाना भी जरूरी है, ताकि नमी बनी रहे।

त्वचा को प्रदूषण के प्रभाव से बचाने के लिए मॉइस्चराइजिंग और सन प्रोटेक्शन दोनों पर ध्यान देना चाहिए। बाहर निकलने से पहले अपनी त्वचा के अनुकूल व्यापक सुरक्षा वाला सनस्क्रीन लगाएं। धूप में अधिक समय बिताना हो तो इसे निर्देशों के अनुसार दोबारा लगाएं। इसके साथ ही चेहरे को धूल और धुएं से बचाने के लिए साफ दुपट्टे, स्कार्फ या मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। आंखों के आसपास की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसलिए वहां किसी भी प्रकार का कठोर उत्पाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेकअप लगाने से पहले त्वचा को मॉइस्चराइज करना और रात में मेकअप पूरी तरह हटाना भी आवश्यक है। प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल भी त्वचा की देखभाल में सहायक हो सकता है। एलोवेरा यानी घृतकुमारी त्वचा को नमी देने और उसे शांत रखने के लिए उपयोगी माना जाता है। इसके जेल का इस्तेमाल करने से पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर परीक्षण कर लेना चाहिए, ताकि किसी तरह की एलर्जी या जलन की आशंका का पता चल सके। चंदन और पुदीने जैसे पारंपरिक पदार्थों का इस्तेमाल भी त्वचा की देखभाल में किया जाता रहा है, लेकिन संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। नीम और तुलसी का नाम भी पारंपरिक सौंदर्य उपचारों में लिया जाता है, हालांकि इनके इस्तेमाल से प्रदूषण का प्रभाव पूरी तरह समाप्त होने की गारंटी नहीं है। किसी भी घरेलू मिश्रण को चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है। नींबू, तेज सुगंध वाले तेल और अन्य तीखे पदार्थ सीधे चेहरे पर लगाने से बचना चाहिए। प्रदूषण का असर केवल चेहरे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बालों और सिर की त्वचा पर भी दिखाई दे सकता है। धूल और धुएं के कण बालों में जमा होकर उन्हें रूखा और बेजान बना सकते हैं। सिर की त्वचा पर पसीने और गंदगी के साथ मिलकर ये कण खुजली और जलन की समस्या बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों में रूसी और बालों के टूटने की समस्या भी अधिक महसूस हो सकती है। इसलिए बालों की सफाई नियमित रूप से करना जरूरी है। अपने बालों और सिर की त्वचा के अनुकूल हल्के शैंपू का इस्तेमाल करें। हर बार शैंपू करने के बाद बालों की लंबाई पर कंडीशनर लगाएं। इससे बालों की नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। बहुत गर्म पानी से बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे बाल और अधिक रूखे हो सकते हैं। बालों की देखभाल के लिए नारियल तेल या अन्य उपयुक्त तेल से हल्की मालिश की जा सकती है। इससे बालों को मुलायम बनाए रखने में मदद मिलती है। तेल लगाने के बाद उसे अपनी सुविधा के अनुसार कुछ समय तक रहने दें और फिर हल्के शैंपू से धो लें। बहुत देर तक तेल लगाए रखना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी सिर की त्वचा तैलीय है या जिन्हें रूसी की समस्या रहती है। सिर में खुजली, लालिमा या घाव होने पर घरेलू मिश्रणों के बजाय त्वचा विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। सिर की त्वचा पर अंडे, सिरके और अन्य घरेलू पदार्थों का मिश्रण लगाने से कुछ लोगों को एलर्जी या जलन हो सकती है, इसलिए ऐसे प्रयोग बिना सावधानी के नहीं करने चाहिए।

प्रदूषण के प्रभाव से बचाव में पानी की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा बनाए रखने से सामान्य शारीरिक क्रियाएं सुचारु रूप से चलती हैं और त्वचा के स्वास्थ्य को भी सहारा मिलता है। दिनभर पर्याप्त स्वच्छ पानी पीना चाहिए। इसके साथ ही मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और पौष्टिक आहार को भोजन में शामिल करना चाहिए। विटामिन सी और ई से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर को एंटीऑक्सीडेंट पोषण प्रदान करते हैं। आंवला, अमरूद, संतरा, नींबू, टमाटर, बादाम और सूरजमुखी के बीज संतुलित आहार का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। ओमेगा-3 फैटी एसिड भी त्वचा के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है। इसके लिए अखरोट, अलसी, चिया सीड्स और उपयुक्त मछलियों का सेवन किया जा सकता है। ओमेगा-6 फैटी एसिड भी कुछ खाद्य तेलों, अनाज और बीजों में पाया जाता है। हालांकि किसी एक खाद्य पदार्थ से प्रदूषण का नुकसान खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए संतुलित खानपान और नियमित दिनचर्या अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, लालिमा और थकान महसूस होना भी आम समस्या है। ऐसे में आंखों को साफ पानी से हल्के हाथों धोना चाहिए। आंखों को बार-बार रगड़ने से बचें, क्योंकि इससे जलन बढ़ सकती है। ठंडे पानी से साफ किए गए मुलायम कपड़े की पट्टी बंद आंखों पर कुछ मिनट रखने से आराम मिल सकता है। आंखों में खुजली या सूखापन लगातार बना रहे तो चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। गुलाब जल या ग्रीन टी का इस्तेमाल आंखों के भीतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना चिकित्सकीय रूप से तैयार किए गए पदार्थ आंखों में संक्रमण या जलन पैदा कर सकते हैं।

ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता पर तेल कंपनियों का दावा सही जांच में मानक के अनुरूप मिली इथेनॉल की मात्रा

नई दिल्ली। कर्नाटक में पेट्रोल में निर्धारित सीमा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने जांच के नतीजे साझा करते हुए दावा किया है कि उनके द्वारा आपूर्ति किए जा रहे ई20 पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। बीपीसीएल ने ग्राहकों की मौजूदगी में किए गए परीक्षण का हवाला देते हुए बताया कि जांचे गए नमूने में 19.9 प्रतिशत इथेनॉल पाया गया। वहीं, एचपीसीएल के अनुसार कर्नाटक में जांचे गए 56 नमूनों में इथेनॉल की औसत मात्रा 19.3 प्रतिशत रही। कंपनियों के इन दावों के बाद पेट्रोल में कथित तौर पर अधिक इथेनॉल मिलाए जाने को लेकर उठे सवालों के बीच ईंधन की गुणवत्ता और जांच प्रक्रिया का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।



बीपीसीएल ने अपने परीक्षण का विवरण देते हुए कहा कि ग्राहक की मौजूदगी में लिए गए और जांचे गए नमूने में इथेनॉल की मात्रा 19.9 प्रतिशत दर्ज की गई। कंपनी ने इसे ईंधन की गुणवत्ता और जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता का प्रमाण बताया। कंपनी का कहना है कि ई20 पेट्रोल निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप तैयार और आपूर्ति किया जा रहा है। ग्राहकों की मौजूदगी में नमूने की जांच का उल्लेख करते हुए कंपनी ने यह संदेश देने की कोशिश की कि ईंधन की गुणवत्ता को लेकर किए जा रहे दावों का आकलन वास्तविक परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए।

इसी क्रम में एचपीसीएल ने भी कर्नाटक में किए गए परीक्षण के आंकड़े सार्वजनिक किए। कंपनी के मुताबिक, राज्य में जांच के लिए लिए गए 56 नमूनों में इथेनॉल की औसत मात्रा 19.3 प्रतिशत पाई गई। एचपीसीएल ने कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को लेकर किसी भी दावे की पुष्टि प्रमाणित वैज्ञानिक जांच और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर होनी चाहिए। कंपनी के अनुसार, केवल आरोपों या अपूर्ण जांच के आधार पर ईंधन की गुणवत्ता पर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। इसके लिए नमूना लेने से लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण तक प्रत्येक चरण में तकनीकी मानकों का पालन जरूरी है।

ई20 पेट्रोल में सामान्य तौर पर 20 प्रतिशत तक इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस ईंधन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक तय किए गए हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने भी कर्नाटक में पेट्रोल में 26 से 31 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाए जाने के आरोपों को खारिज किया था। मंत्रालय के अनुसार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल और एचपीसीएल की ओर से आपूर्ति किया जा रहा ई20 पेट्रोल भारतीय मानक आईएस 17021 के अनुरूप है। मंत्रालय ने देशभर में की गई निगरानी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लिए गए नमूनों में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर पाई गई है।

मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, देश के 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कुल 893 नमूने लिए गए थे। इन सभी नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 19 से 21 प्रतिशत के निर्धारित दायरे में मिली। यह आंकड़ा सरकार और तेल कंपनियों की ओर से ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता के समर्थन में प्रमुख आधार के रूप में पेश किया गया है। मंत्रालय का कहना है कि देशव्यापी निगरानी में निर्धारित मानकों से अधिक इथेनॉल मिलने की पुष्टि नहीं हुई। इससे कर्नाटक में पेट्रोल में 26 से 31 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाने के दावे पर सवाल खड़े हुए हैं।

हालांकि, इस पूरे मामले में मंत्रालय ने केवल परीक्षण के नतीजों पर ही नहीं, बल्कि नमूने एकत्र करने और उनकी जांच की प्रक्रिया पर भी जोर दिया है। मंत्रालय के अनुसार, पेट्रोल के नमूने लेने, उन्हें सुरक्षित रखने, संबंधित प्रयोगशाला तक पहुंचाने और उनका परीक्षण करने के लिए निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। यदि नमूने लेने या उन्हें प्रयोगशाला तक पहुंचाने के दौरान तय मानकों का पालन नहीं होता है, तो जांच के नतीजों की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसलिए ईंधन में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक और प्रमाणित परीक्षण प्रक्रिया जरूरी है। कर्नाटक में अक्टूबर के दौरान की गई जांच को लेकर मंत्रालय ने सवाल उठाए थे। उसका कहना था कि संबंधित नमूनों की पूरी जानकारी और प्रयोगशाला की विस्तृत रिपोर्ट तेल कंपनियों को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। ऐसे में 26 से 31 प्रतिशत इथेनॉल मिलाए जाने के दावों की निर्धारित तकनीकी प्रक्रिया के तहत पुष्टि नहीं हो सकी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ईंधन की गुणवत्ता से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए नमूनों की पहचान, संग्रह की परिस्थितियों और परीक्षण रिपोर्ट का उपलब्ध होना आवश्यक है। केवल प्रारंभिक दावों के आधार पर पूरे ईंधन आपूर्ति तंत्र की गुणवत्ता पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए।

ई20 पेट्रोल को लेकर उठे विवाद ने ईंधन की गुणवत्ता की नियमित निगरानी और जांच व्यवस्था के महत्व को भी सामने ला दिया है। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के मामले में निर्धारित अनुपात बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि वाहन के इंजन और ईंधन प्रणाली के अनुकूलता मानकों को ध्यान में रखकर ही मिश्रण की सीमा तय की जाती है। ऐसे में तेल कंपनियों और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि पेट्रोल की आपूर्ति से पहले और उसके बाद भी गुणवत्ता की जांच की व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। उपभोक्ताओं को भी ईंधन की गुणवत्ता को लेकर किसी तरह की शिकायत होने पर प्रमाणित जांच और आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से उसका समाधान तलाशना चाहिए।

फिलहाल बीपीसीएल और एचपीसीएल की ओर से जारी आंकड़ों तथा मंत्रालय की देशव्यापी निगरानी रिपोर्ट के आधार पर सरकारी तेल कंपनियों ने ई20 पेट्रोल की गुणवत्ता को निर्धारित मानकों के अनुरूप बताया है। कर्नाटक में अधिक इथेनॉल मिलाने के आरोपों को मंत्रालय ने भी स्वीकार नहीं किया है। इस मामले में कंपनियों का जोर इस बात पर है कि ईंधन की गुणवत्ता का आकलन वैज्ञानिक परीक्षण और प्रमाणित आंकड़ों से किया जाना चाहिए। 893 नमूनों में निर्धारित सीमा के भीतर इथेनॉल मिलने का दावा सरकार की इसी स्थिति को मजबूत करता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के करकमलों से अहमदाबाद में 1,400 करोड़ रुपए से अधिक के जनहितकारी विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ

▸▸ केन्द्रीय गृह मंत्री का गुजरात को दिसंबर 2028 तक ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान

▸▸ ड्रग्स के दुष्प्रभाव के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी; 1 दिसंबर के बाद नागरिक '1033' नंबर पर निःसंकोच जानकारी दे सकेंगे : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

▸▸ प्रधानमंत्री की प्रेरणा से मनाए जा रहे इस विकास उत्सव और जनकल्याणकारी परियोजनाओं से नागरिकों की दिवाली अधिक रोशन हुई : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ नूतन वर्ष के प्रारंभ से पूर्व गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को सुविधाजनक एवं जनकल्याणकारी विकास कार्यों की भेंट

▸▸ सरखेज-गांधीनगर हाईवे पर अनुमानित 464 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 6-लेन इस्कॉन-साणंद एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण

▸▸ वाडज रामापीर के टेकरा क्षेत्र में आवासों और दुकानों का कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ एवं चाबियाँ वितरित करने से गरीब तथा जरूरतमंद परिवारों में खुशी की लहर



गांधीनगर : त्योहारी सीजन और नए साल से पूर्व अहमदाबाद शहर के नागरिकों को सुविधा और समृद्धि की अनूठी भेंट देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सोमवार को अहमदाबाद महानगर पालिका तथा भारत सरकार के सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में शुरू किए गए अनुमानित 1,400 करोड़ रुपए से अधिक के लगभग 30 जनहितकारी कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

विभिन्न जनकल्याणकारी परियोजनाओं के लोकार्पण एवं भूमिपूजन के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, प्रभारी मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, शहरी विकास राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला, महापौर श्री हितेशभाई बारोट, सांसद श्री हसमुखभाई पटेल और श्री दिनेशभाई मकवाणा, निकोल के विधायक एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीशभाई विश्वकर्मा उपस्थित रहे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने वाडज रामापीर के टेकरा स्लम क्षेत्र के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्मित पक्के मकानों सहित 9,000 से अधिक आवासों और 16 दुकानों का कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ कर जरूरतमंदों को घरों की चाबियाँ सौंपीं। इस अवसर पर एसजी हाईवे पर यातायात की समस्या को कम करने वाले अनुमानित 464 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस्कॉन से साणंद तक के 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर का भी लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह के करकमलों से अहमदाबाद टूरिज्म के लोगो का अनावरण किया गया तथा शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अहमदाबाद महानगर पालिका के सफाईकर्मियों को भी सम्मानित किया गया। तीन लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से केन्द्रीय गृह मंत्री ने घर की चाबियाँ सौंपीं। इसके अलावा; शहर की पेयजल संबंधी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जासपुर में नवनिर्मित 200 एमएलडी क्षमता वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तथा 7.40 किलोमीटर लंबी ट्रंक मेन लाइन परियोजना का भी लोकार्पण किया गया। साथ ही; साबरमती रिवरफ्रंट पर 62.31 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार होने वाले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तथा अहमदाबाद महानगर पालिका के विभिन्न वार्डों में सीनियर सिटीजन पार्क, योगा कॉर्नर, ड्रेनेज नेटवर्क, बस डिपो/टर्मिनस, स्लम रिडेवलपमेंट, राइजिंग मेन तथा स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन जैसी महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी संपन्न हुआ।

इस अवसर पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देश और राज्य के युवाओं की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं की आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने वाले ड्रग्स के दुष्प्रभाव को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई गई है। गुजरात को दिसंबर 2028 तक ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने की सामूहिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 1 दिसंबर 2026 से 1033 डायल-फ्री हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम शुरू किया जाएगा।

उन्होंने नागरिकों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि यदि आसपास कहीं भी ड्रग्स की बिक्री या सेवन होता दिखाई दे, तो 1 दिसंबर 2026 के बाद नागरिक निःसंकोच 1033 नंबर पर जानकारी दें, ताकि सख्त से सख्त कार्रवाई करके इसके जिम्मेदार लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया जा सके।

इसके साथ ही; उन्होंने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत को याद करते हुए कहा कि पहले रामापीर के टेकरा क्षेत्र में जहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, उसी स्लम क्षेत्र के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आज आधुनिक सुविधाओं से युक्त पक्के मकानों और दुकानों का कम्प्यूटरीकृत ड्रॉ तथा चाबियों के वितरण से गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊँचा हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में झुग्गी-झोपड़ियों के स्थान पर पक्के घर उपलब्ध कराने की योजना से आज लाखों गरीबों के जीवन में नई रोशनी आई है।

विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उपस्थित सभी लोगों को दीपावली पर्व की शुभकानाएँ देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा विकास को पर्व के रूप में मनाने की शुरू की गई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दिवाली और नए साल के अवसर पर अरबों रुपए के सुविधाजनक कार्यों की भेंट देकर शहरवासियों की दिवाली को और अधिक प्रकाशमय बनाया है।

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि नवनिर्मित इस्कॉन-साणंद फ्लाईओवर से प्रतिदिन आवागमन करने वाले लाखों लोगों को ट्रैफिक से बड़ी राहत मिलेगी, जबकि बोपल-घुमा क्षेत्र में बारिश के पानी की निकासी के लिए पंपिंग स्टेशन का काम शुरू होने से जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन, नए आपराधिक कानून और नक्सलवाद के खात्मे जैसे फैसलों से देश सुरक्षित बना है। इसके अलावा; देश के पहले सहकारिता मंत्री के रूप में श्री अमित शाह ने छोटे से छोटे व्यक्ति को सहकारिता से जोड़कर समृद्धि की नई दिशा दी है और आवास योजनाओं के माध्यम से गरीबों को पक्के मकान मिलने से उनका जीवन स्तर ऊँचा हुआ है।

इस अवसर पर महापौर श्री हितेशभाई बारोट ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री के करकमलों से आज विभिन्न विकास परियोजनाओं की भेंट अहमदाबाद लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों को मिली है। उन्होंने कहा कि 9 हजार से अधिक लोगों को अपना पक्का घर मिलने जा रहा है। यह नई शुरुआत उनके परिवारों के जीवन में खुशहाली लाएगी। शहर के अनुमानित 12 लाख से अधिक परिवारों के लिए पेयजल सुविधाओं सहित स्मार्ट स्कूल, आँगनबाड़ी, सीनियर सिटीजन पार्क सहित विभिन्न कार्यों का आज लोकार्पण एवं शिलान्यास हुआ है, जो शहरवासियों के कल्याण में वृद्धि करेगा।

विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के अवसर पर गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायक, अहमदाबाद महानगर पालिका की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल, अहमदाबाद महानगर पालिका आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, अग्रणी श्री प्रेरकभाई शाह, अहमदाबाद महानगर पालिका के पदाधिकारी, विभिन्न समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा स्थानीय पार्षद उपस्थित रहे।

641.93 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पित किए गए प्रमुख जनहितकारी कार्य :

▸▸ जासपुर वाटर वर्क्स में 200 एमएलडी क्षमता वाला नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट।

▸▸ अहमदाबाद महानगर पालिका की बिजली संबंधी जरूरतों के लिए 30 मेगावाट का ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट।

▸▸ जासपुर डब्ल्यूयूटीपी से के. डी. अस्पताल तक 2500 मिमी व्यास की ट्रंक मेन पाइपलाइन।

▸▸ वाडज रामापीर के टेकरा (सेक्टर-5 और 1) में कुल 1232 पक्के आवासों और 16 दुकानों का लोकार्पण एवं ड्रॉ।

▸▸ उत्तर-पश्चिम जोन के जगतपुर में 15 एमएलडी क्षमता वाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)।

▸▸ गोता बंधन ट्रायएंगल में इन्फिल्ट्रेशन टैंक और 60 एमएलडी पंपिंग स्टेशन।

▸▸ नया राणिप (टी.पी. 66/ए) और चांदलोडिया में नए वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन।

▸▸ केशवनगर और मेमनगर फायर स्टेशन क्षेत्र के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनों का विस्तार।

▸▸ राणिप बस स्टैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन में 20 लाख लीटर क्षमता वाली ओवरहेड टंकी।

▸▸ गोता (साइंस सिटी) और त्रागड में नवनिर्मित अर्बन हेल्थ सेंटर।

▸▸ जोधपुर में नॉलेज हब (लाइब्रेरी), 6 महानगर पालिका स्मार्ट स्कूल और सीनियर सिटीजन पार्क।

▸▸ भारत सरकार की 'SMILE' योजना अंतर्गत अहमदाबाद को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए आश्रयगृह का शुभारंभ।

382.08 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास किए गए प्रमुख जनहितकारी कार्य :

▸▸ नए वाडज (हनुमानपुरा चाली और परीक्षितलाल नगर) में 2002 आवासों और 84 दुकानों की पुनर्वास परियोजना।

▸▸ साबरमती रिवरफ्रंट के उस्मानपुरा गार्डन में क्लाइमेट-कंट्रोल्ड डोम के साथ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट (62.31 करोड़ रुपए)।

▸▸ सरखेज, मकरबा और ओकाफ (टीपी 87, 88, 201) क्षेत्रों में आधारभूत ड्रेनेज नेटवर्क लाइन बिछाने का कार्य।

▸▸ बोपल-घुमा रत्ना तालाब के पास 1400 मिमी राइजिंग मेन के साथ स्टॉर्म वाटर पंपिंग स्टेशन।

▸▸ घुमा (टीपी-2) में इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा युक्त बस डिपो और टर्मिनस।

▸▸ चांदलोडिया (त्रागड) में सीनियर सिटीजन पार्क तथा योगा कॉर्नर का निर्माण।

आईआरआईसीईएन पुणे को कौशल विकास मंत्रालय ने दिया उत्कृष्टता केंद्र का दर्जा



नई दिल्ली। भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान (आईआरआईसीईएन), पुणे ने कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने संस्थान को अपनी 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल्स' (सीओई-स्किल्स) पहल के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची में शामिल किया है। इस मान्यता से रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण, तकनीकी दक्षता और क्षमता निर्माण के लिए संस्थान की भूमिका को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसे रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों को आधुनिक इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित करने और कौशल विकास की व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई दिल्ली स्थित कौशल भवन में 2 नवंबर को आयोजित समारोह के दौरान केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सचिव ने आईआरआईसीईएन को मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया। संस्थान की ओर से वरिष्ठ प्रोफेसर श्रीरंग कांबले ने यह प्रमाणपत्र प्राप्त किया। इस अवसर पर संस्थान को कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दिए जाने की औपचारिक पुष्टि हुई। मंत्रालय की इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और व्यावसायिक दक्षता को बढ़ावा देने वाले संस्थानों की पहचान कर उन्हें उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करना है।

आईआरआईसीईएन भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रशिक्षण से जुड़ा प्रमुख संस्थान है। रेलवे के बुनियादी ढांचे के निर्माण, रखरखाव और तकनीकी प्रबंधन में सिविल इंजीनियरिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रेल पटरियों, पुलों, भवनों और अन्य संरचनाओं की गुणवत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित और कुशल तकनीकी मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। ऐसे में संस्थान को मिली यह मान्यता रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक क्षमता को और मजबूत बनाने में सहायक हो सकती है।

इस मान्यता के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आधुनिक तकनीकी जरूरतों के अनुरूप विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। बदलती इंजीनियरिंग तकनीकों, निर्माण पद्धतियों और रेलवे के विस्तारित बुनियादी ढांचे के बीच कर्मचारियों को लगातार नए कौशल से लैस करना आवश्यक है। आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान, तकनीकी समस्याओं का समाधान और कार्यस्थल पर दक्षता बढ़ाने जैसे पहलुओं में प्रशिक्षण संस्थानों की भूमिका अहम होती है। आईआरआईसीईएन की यह उपलब्धि इसी दिशा में उसके योगदान को रेखांकित करती है।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल्स' पहल के तहत मान्यता मिलना संस्थान के लिए केवल प्रमाणपत्र हासिल करने तक सीमित उपलब्धि नहीं है, बल्कि इससे भविष्य में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और क्षमता निर्माण को नई दिशा देने का अवसर भी मिलेगा। रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों को आधुनिक इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से परिचित कराने और बदलती कार्य आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी दक्षता बढ़ाने में संस्थान की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। आईआरआईसीईएन पुणे को मिली यह मान्यता सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक कौशल विकास के क्षेत्र में संस्थान के प्रयासों की पहचान है। इससे रेलवे के प्रशिक्षण तंत्र को मजबूती मिलने के साथ सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता और आधुनिक तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी मजबूत होंगी।

थाइलैंड और मलेशिया के रबर दस्तानों पर पांच साल तक लग सकता है डंपिंग-रोधी शुल्क

नई दिल्ली। भारत के घरेलू चिकित्सा उपकरण उद्योग को विदेशी कंपनियों से मिलने वाली मूल्य प्रतिस्पर्धा से राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) ने थाइलैंड और मलेशिया से आयात होने वाले चिकित्सा उपयोग के रबर दस्तानों पर पांच साल तक डंपिंग-रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इन देशों से आने वाले दस्तानों पर प्रति एक लाख दस्तानों के हिसाब से 442 से 565 अमेरिकी डॉलर तक शुल्क लगाया जा सकता है। डीजीटीआर की जांच में पाया गया है कि संबंधित देशों के विनिर्माताओं की ओर से भारतीय बाजार में इन दस्तानों की बिक्री कथित तौर पर सामान्य मूल्य से कम कीमत पर की जा रही थी, जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा है। हालांकि, शुल्क लगाने को लेकर अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय को करना है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने थाइलैंड और मलेशिया से चिकित्सा उपयोग के रबर दस्तानों के आयात की जांच के बाद यह सिफारिश की है। जांच में प्राधिकरण ने पाया कि इन देशों से आने वाले दस्ताने भारतीय बाजार में कम कीमत पर बेचे जा रहे थे। आयातित उत्पादों की कीमतों और घरेलू उद्योग पर उनके प्रभाव का आकलन करने के बाद डीजीटीआर ने माना कि इस तरह के आयात से भारत में दस्ताने बनाने वाले उद्योग को नुकसान पहुंचा है। विशेष रूप से शुरुआती दौर में काम कर रहे घरेलू विनिर्माताओं के लिए कम कीमत वाले विदेशी उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा और बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति को संतुलित करने के लिए शुल्क लगाने की अनुशंसा की गई है।

चिकित्सा उपयोग में आने वाले रबर दस्तानों की मांग अस्पतालों, नर्सिंग होम, जांच प्रयोगशालाओं और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार बनी रहती है। चिकित्सा कर्मियों और मरीजों की सुरक्षा के लिहाज से इन दस्तानों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ इनकी उपलब्धता और गुणवत्ता भी आवश्यक है। ऐसे उत्पादों के बाजार में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना सरकार की औद्योगिक नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। यदि विदेशी कंपनियां अपने उत्पादों को असामान्य रूप से कम कीमत पर भारतीय बाजार में बेचती हैं, तो घरेलू कंपनियों के लिए उत्पादन लागत निकालना और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

डीजीटीआर के अनुसार, प्रस्तावित डंपिंग-रोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू निर्माताओं को सस्ते आयात से होने वाले नुकसान से बचाना और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बहाल करना है। प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं और उत्पादों का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कोई महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है। इस तरह की सिफारिशों में घरेलू उद्योग के संरक्षण के साथ यह भी देखा जाता है कि शुल्क का असर बाजार में उत्पादों की उपलब्धता और उपयोगकर्ताओं पर कितना पड़ सकता है। डीजीटीआर ने अपने आकलन के आधार पर माना है कि प्रस्तावित कदम से घरेलू उद्योग को राहत मिल सकती है।

इस मामले में जांच नवको इंडस्ट्रीज और वाडी सर्जिकल्स की ओर से किए गए आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। इन कंपनियों ने थाइलैंड और मलेशिया से चिकित्सा उपयोग के रबर दस्तानों के आयात के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि संबंधित देशों के उत्पाद भारतीय बाजार में कम कीमत पर बेचे जा रहे हैं, जिससे देश के घरेलू विनिर्माताओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आवेदन के बाद डीजीटीआर ने आयात और घरेलू उद्योग पर उसके प्रभाव से जुड़े पहलुओं की जांच की। जांच पूरी होने के बाद प्राधिकरण ने पांच साल के लिए शुल्क लगाने की सिफारिश की है। हालांकि, डीजीटीआर की सिफारिश अपने आप में शुल्क लागू होने का अंतिम आदेश नहीं है। इस पर अंतिम निर्णय वित्त मंत्रालय को लेना होगा।

डंपिंग-रोधी शुल्क का उद्देश्य विदेशी उत्पादों के आयात को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उन स्थितियों में घरेलू उद्योग को संरक्षण देना है, जब आयातित वस्तुओं की कीमत सामान्य बाजार मूल्य से कम पाई जाती है और उससे देश के उत्पादकों को नुकसान पहुंचता है। यह शुल्क संबंधित उत्पादों और देशों के लिए निर्धारित किया जाता है। इसका निर्धारण जांच में सामने आए तथ्यों और मूल्य अंतर के आधार पर होता है। थाइलैंड और मलेशिया से आने वाले चिकित्सा रबर दस्तानों के मामले में प्रति एक लाख दस्तानों पर 442 से 565 डॉलर तक शुल्क लगाने की सिफारिश इसी प्रक्रिया का हिस्सा है।

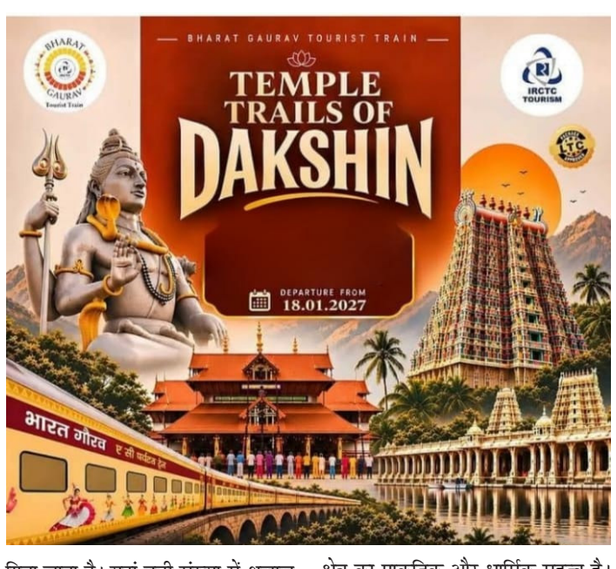
इसी बीच डीजीटीआर ने चीन से आयात होने वाली अनट्रीटेड फ्यूम्ड सिलिका पर भी डंपिंग-रोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की है। प्राधिकरण ने इस उत्पाद पर 1,296 अमेरिकी डॉलर प्रति टन शुल्क जारी रखने का प्रस्ताव दिया है। फ्यूम्ड सिलिका एक औद्योगिक पदार्थ है, जिसका उपयोग कई तरह के उत्पादों और विनिर्माण प्रक्रियाओं में किया जाता है। दवा, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि रसायन सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में इसकी कीमत और आयात की स्थिति का असर संबंधित उद्योगों पर भी पड़ सकता है।

दक्षिण भारत के नौ तीर्थस्थलों की यात्रा कराएगी भारत गौरव ट्रेन, 18 जनवरी से होगा सफर शुरू

मुंबई। दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक पर्यटन केंद्रों की सैर करने की योजना बना रहे यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) विशेष यात्रा पैकेज लेकर आया है। आईआरसीटीसी के पश्चिम क्षेत्र, मुंबई की ओर से 'टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण' नाम से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 18 जनवरी 2027 को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) से अपनी यात्रा शुरू करेगी। 11 रातें और 12 दिनों के इस विशेष पर्यटन कार्यक्रम में यात्रियों को दक्षिण भारत के नौ प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस यात्रा के माध्यम से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक ही पैकेज में कई प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन के साथ ऐतिहासिक स्मारकों, समुद्र तटों और सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। पैकेज का शुरुआती किराया प्रति यात्री 20,420 रुपये निर्धारित किया गया है।

आईआरसीटीसी की इस विशेष ट्रेन में दक्षिण भारत के अलग-अलग राज्यों में स्थित प्रमुख तीर्थस्थलों को यात्रा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इनमें गोकर्ण, मुरुडेश्वर, गुरुवायुर, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, कांचीपुरम और महाबलीपुरम प्रमुख हैं। इन सभी स्थानों का धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। यात्रा के दौरान यात्रियों को प्राचीन मंदिरों की स्थापत्य कला, समुद्र तटों की प्राकृतिक सुंदरता और दक्षिण भारतीय परंपराओं को जानने-समझने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए यह यात्रा उपयोगी हो सकती है, जो सीमित समय में दक्षिण भारत के कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं।

यात्रा की शुरुआत में गोकर्ण और मुरुडेश्वर जैसे प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। कर्नाटक के गोकर्ण में स्थित महाबलेश्वर मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में शामिल है। धार्मिक आस्था के साथ-साथ यह स्थान अपने समुद्र तटों और प्राकृतिक वातावरण के लिए भी जाना जाता है। यहां पर्यटकों को प्रसिद्ध ओम बीच देखने का अवसर मिलेगा। इसके बाद मुरुडेश्वर में भगवान शिव के भव्य मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। समुद्र तट के निकट स्थित यह मंदिर अपनी विशाल शिव प्रतिमा और आकर्षक परिवेश के कारण श्रद्धालुओं के साथ पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय है। इस पड़ाव में धार्मिक दर्शन के साथ समुद्र और आसपास के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का अवसर मिलेगा। यात्रा का अगला प्रमुख पड़ाव केरल का गुरुवायुर होगा, जहां प्रसिद्ध गुरुवायुर मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित यह मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख वैष्णव तीर्थस्थलों में



गिना जाता है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके बाद यात्रा तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुंचेगी। यहां स्थित श्री रामनाथस्वामी मंदिर हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थस्थलों में से एक है और चार धाम यात्रा में भी इसका विशेष महत्व माना जाता है। मंदिर के विशाल गलियारे, प्राचीन धार्मिक परंपराएं और स्थापत्य कला पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। रामेश्वरम प्रवास के दौरान यात्रियों को धनुषकोडी का भ्रमण भी कराया जाएगा। समुद्र से घिरे इस क्षेत्र का प्राकृतिक और धार्मिक महत्व है। रामेश्वरम की यह यात्रा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी।

इसके बाद पर्यटक मदुरै पहुंचेंगे, जहां प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, ऊंचे गोपुरम और सुंदर शिल्पकारी के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशिष्ट पहचान को समझने के लिहाज से भी यह स्थान महत्वपूर्ण है। यात्रा का एक अन्य प्रमुख पड़ाव कन्याकुमारी होगा, जहां यात्रियों को कुमारी अम्मन मंदिर के दर्शन का अवसर मिलेगा। इसके अलावा विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गांधी मंडपम और प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट भी यात्रा कार्यक्रम में शामिल हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी अपनी समुद्री भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक दृश्यों के लिए विशेष पहचान रखता है। यहां समुद्र के किनारे सूर्यास्त का दृश्य पर्यटकों के लिए यादगार अनुभव हो सकता है।

यात्रा के दौरान तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथस्वामी मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर श्रीवैष्णव परंपरा के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में शामिल है। इसके साथ ही तंजावुर मंदिर का भ्रमण भी कार्यक्रम में रखा गया है, जो दक्षिण भारत की प्राचीन स्थापत्य और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इन मंदिरों की विशाल संरचनाएं, कलात्मक नक्काशी और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस यात्रा को केवल धार्मिक भ्रमण तक सीमित नहीं रहने देंगी, बल्कि यात्रियों को दक्षिण भारत के इतिहास और कला से भी परिचित कराएंगी।

इसके बाद यात्रा कांचीपुरम पहुंचेगी, जिसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। यहां कामाक्षी अम्मन मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर और श्री वरदराजा पेरुमल मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। कांचीपुरम शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के प्रमुख धार्मिक केंद्रों में शामिल है। यहां के मंदिर अपनी प्राचीनता, धार्मिक मान्यताओं और द्रविड़ स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। यात्रा का अंतिम प्रमुख पर्यटन पड़ाव महाबलीपुरम होगा। यहां प्रसिद्ध शोर मंदिर और कृष्णा बटरबॉल का भ्रमण कराया जाएगा। समुद्र तट के समीप स्थित शोर मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है, जबकि कृष्णा बटरबॉल अपनी अनोखी प्राकृतिक संरचना के कारण पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इस तरह यात्रा में धार्मिक स्थलों के साथ ऐतिहासिक और प्राकृतिक पर्यटन को भी समान महत्व दिया गया है।

आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा और बजट को ध्यान में रखते हुए तीन श्रेणियों में पैकेज तैयार किए हैं। इकोनॉमी श्रेणी में स्लीपर क्लास से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए प्रति व्यक्ति किराया 20,420 रुपये निर्धारित किया गया है। स्टैंडर्ड श्रेणी में थर्ड एसी से यात्रा करने के लिए 32,770 रुपये और कंफर्ट श्रेणी में सेकंड एसी से यात्रा करने के लिए 42,940 रुपये प्रति यात्री खर्च करने होंगे। अलग-अलग श्रेणियों के विकल्प होने से यात्री अपनी सुविधा और बजट के अनुसार पैकेज का चयन कर सकेंगे। पांच से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी विशेष पैकेज दरें उपलब्ध कराई गई हैं।

पैकेज में केवल रेल यात्रा ही नहीं, बल्कि पूरे भ्रमण के दौरान आवश्यक सुविधाओं को भी शामिल किया गया है। इसके तहत होटल में ठहरने की व्यवस्था, शाकाहारी भोजन, स्थानीय पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए बस परिवहन, यात्रा बीमा और ट्रेन में सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। लागू कर भी पैकेज में शामिल हैं। यात्रियों को अलग-अलग स्थानों पर होटल और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था स्वयं करने की आवश्यकता नहीं होगी। आईआरसीटीसी की ओर से यात्रा की निर्धारित योजना के अनुसार इन सुविधाओं का प्रबंध किया जाएगा। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत करीब 33 प्रतिशत की रियायत भी पैकेज की घोषित दरों में शामिल है, जिससे यात्रियों को निर्धारित किराये पर यात्रा का अवसर मिलेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में चढ़ने और उतरने के लिए कई स्टेशनों का विकल्प भी दिया गया है। सीएसएमटी के अलावा ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, सातारा, मिरज और बेलगावी स्टेश